* 19th Year
* Issue: 272
* 09.02.2026 (MONDAY)
* ROURKELA
* R.N.I. No. ORIHIN/2006/18978
* (Pages-6)
* Price:2.00

e-paper-www.thekalingasamachar.com

दैनिक कलिंग समाचार

The kalingasamachar

प्रकाशक एवं संपादक : प्रकाश कुमार धल

Published From ODISHA, JHARKHAND & CHHATTISHGARH

एक-दूसरे से जुड़ी है भारत-मलेशिया की समृद्धिः पीएम मोदी और अनवर इब्राहिम के बीच उच्च स्तरीय वार्ता, कई अहम समझौते हुए

नयी दिल्ली ०८/०२ (संवाददाता):प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दो दिवसीय मलेशिया यात्रा के दूसरे दिन भारत और मलेशिया के बीच रिश्तों का एक नया अध्याय शुरू हुआ। प्रधानमंत्री मोदी और उनके मलेशियाई समकक्ष अनवर इब्राहिम के बीच रविवार को प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई, जिसमें दोनों नेताओं ने इस बात पर जोर दिया कि नई दिल्ली और कुआलालंपुर की समृद्धि एक-दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई है।

प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि भारत और मलेशिया दो महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी हैं, और वैश्विक अस्थिरता के बीच उन्हें अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि उनकी दो दिवसीय यात्रा का मुज़्य संदेश भारत और मलेशिया के बीच हर संभव क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करना है, और उन्होंने इब्राहिम को उनके आगमन पर मिले शानदार स्वागत के लिए धन्यवाद दिया।उन्होंने कहा कि मलेशिया में लगभग तीन मिलियन भारतीय मूल के लोग रहते हैं, जो दोनों देशों के बीच एक %जीवित पुल% हैं। अपनी टिप्पणी में, क्करू मोदी ने एसोसिएशन ऑफ साउथईस्ट एशियन नेशंस (आसियान) की सफल अध्यक्षता के लिए इब्राहिम को बधाई दी, और कहा कि कुआलालंपुर के सहयोग से यह मंच और मजबूत होगा।

समाचार एजेंसी‚ह्द्ध के अनुसार, भारतीय नेता ने कहा, आज, हमारा सहयोग कृषि और विनिर्माण से लेकर स्वच्छ ऊर्जा और सेमीकंडज़्टर तक हर क्षेत्र में गहरा हो रहा है।ऋ हम कौशल विकास और क्षमता निर्माण में भी महत्वपूर्ण भागीदार हैं। हमारा रक्षा और सुरक्षा सहयोग भी लगातार मजबूत हो रहा है।

दोनों नेताओं के बीच बातचीत के बाद, भारत और मलेशिया ने कई रूश्व (समझौता ज्ञापन) पर हस्ताक्षर किए, जिसमें इब्राहिम ने कहा कि नई दिल्ली ने वैश्विक व्यापार और आर्थिक मोर्चे पर शानदार वृद्धि दर्ज की है। एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, मलेशियाई प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश व्यापार, निवेश, कनेज़्टिविटी और रक्षा में अपने बीच सहयोग का विस्तार करना जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि ये रूश्व भारत और मलेशिया के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थे, जिनके 1957 से लंबे समय से संबंध हैं। इब्राहिम ने कहा कि दोनों पक्ष आतंकवाद विरोधी, खुफिया जानकारी साझा करने और समुद्री सुरक्षा में भी सहयोग मजबूत करेंगे। उन्होंने कहा, मुझे इस अवसर पर क्करू मोदी को दुनिया भर में सभी शांति प्रयासों का समर्थन करने की उनकी दृढ़ प्रतिबद्धता के लिए अपना सज़्मान और धन्यवाद व्यक्त करना चाहिए, चाहे वह यूक्रेन, रूस या मध्य पूर्व के मामले में हो, विशेष रूप से गाजा में, शांति प्रक्रिया का समर्थन करने की उनकी प्रतिबद्धता स्पष्ट है और निश्चित रूप से इसलिए मुझे अपनी प्रशंसा व्यक्त करनी चाहिए।प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, पीएम मोदी ने ज़ोर देकर कहा कि भारत और मलेशिया रक्षा सहयोग को और ज़्यादा व्यापक बनाएंगे, और दुनिया के लिए इंडो-पैसिफिक क्षेत्र के महत्व पर भी ज़ोर दिया। इसके अलावा, दोनों देश सेमीकंडज़्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (ह्द्ध), डिजिटल टेज़्नोलॉजी और स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में भी अपनी साझेदारी का विस्तार करेंगे।प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत‚स्श्वह्र की केंद्रीयता को बहुत प्राथमिकता देता है। उन्होंने कहा कि भारत और मलेशिया का मानना ??है कि दुनिया की मौजूदा चुनौतियों से निपटने के लिए वैश्विक संस्थानों में सुधार ज़रूरी है। इसके अलावा, आतंकवाद से निपटने में कोई दोहरा मापदंड नहीं हो सकता, उन्होंने यह भी कहा।उन्होंने आगे कहा भारत-मलेशिया संबंध सच में बहुत खास हैं। हम समुद्री पड़ोसी हैं। सदियों से हमारे दोनों देशों के लोगों के बीच गहरे संबंध रहे हैं। आज, मलेशिया दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है जहाँ भारतीय मूल की आबादी रहती है।

हमारी सज़्यताएँ साझा सांस्कृतिक विरासत और लोकतांत्रिक मूल्यों से जुड़ी हुई हैं।उन्होंने आगे कहा सुरक्षा क्षेत्र में, हम आतंकवाद विरोधी, खुफिया जानकारी साझा करने और समुद्री सुरक्षा में सहयोग को मज़बूत करेंगे। हम रक्षा सहयोग को भी और ज़्यादा व्यापक बनाएंगे।‚ह्द्ध और डिजिटल टेज़्नोलॉजी के साथ-साथ, हम सेमीकंडज़्टर, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा में भी अपनी साझेदारी को और आगे बढ़ाएंगे।

केंद्रीय गृहमंत्री ने छज़ीसगढ़ में विभिन्न विकास कार्यों पर भी समीक्षा बैठक की

रायपुर ०८/०२ (संवाददाता): केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज छज़ीसगढ़ की राजधानी रायपुर में वामपंथी उग्रवाद पर सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। साथ ही, गृह मंत्री ने छज़ीसगढ़ में विभिन्न विकास कार्यों पर भी एक समीक्षा बैठक की। इन बैठकों में छज़ीसगढ़ के मुज़्यमंत्री विष्णु देव साय, उप-मुज़्यमंत्री विजय शर्मा, केन्द्रीय गृह सचिव, आसूचना ज़्यूरो के निदेशक, गृह मंत्रालय के विशेष सचिव (आंतरिक सुरक्षा), छज़ीसगढ़ के मुज़्य सचिव, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, सीमा सुरक्षा बल, भारत-तिज़्बत सीमा पुलिस के महानिदेशक तथा छज़ीसगढ़, तेलंगाना, झारखंड, ओडिशा और महाराष्ट्र के गृह सचिव एवं पुलिस महानिदेशक उपस्थित थे।बैठक को संबोधित करते हुए केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि केन्द्र और छज़ीसगढ़ सरकार की सुरक्षा केन्द्रित रणनीति, इंफ्रास्ट्रक्चर, नज़सल फाइनेंशियल नेटवर्क पर प्रहार व आत्मसमर्पण नीति के सकारात्मक परिणाम आए हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि आगामी 31 मार्च से पहले नज़सलवाद पूरी तरह समाप्त हो रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि छज़ीसगढ़ कभी नज़सली हिंसा का गढ़ था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही डबल इंजन सरकार में यह अब विकास का पर्याय बन चुका है। उन्होंने कहा कि छज़ीसगढ़ के युवा खेल, फॉरेंसिक और तकनीकी शिक्षा को गति देते हुए अपनी संस्कृति व परंपराओं को भी सहेज रहे हैं।अमित शाह ने कहा कि डबल इंजन सरकार देश से माओवाद की समस्या को पूरी तरह समाप्त करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार में नज़सलवाद अंत के कगार पर पहुँच चुका है और 31 मार्च 2026 से पहले देश पूरी तरह नज़सल-मुक्त हो जाएगा। गृह मंत्री ने कहा कि कई पीढ़ियों को गरीबी और अशिक्षा के अंधकार में धकेलने वाले नज़सलवाद से देश जल्द ही निजात पाने वाला है। श्री शाह ने कहा कि माओवादियों के खिलाफ चल रही लड़ाई बिखरी हुई नहीं होनी चाहिए। विभिन्न राज्यों और केन्द्रीय एजेंसियों के बीच सुचारू समन्वय की आवश्यकता पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि शेष बचे माओवादियों को अन्य राज्यों में भागने नहीं दिया जाना चाहिए। केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि छज़ीसगढ़ ने सुरक्षा और विकास दोनों मोर्चों पर उल्लेखनीय प्रगति की है। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि नज़सल प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को विकास के समान अवसर प्राप्त हों।

भागे नहीं, संघर्ष करें..., बांग्लादेशी हिन्दुओं को मोहन भागवत की सलाह

मुंबई ०८/०२ (संवाददाता): आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने रविवार को मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं की सुरक्षा पर कड़ा और साफ संदेश दिया। उन्होंने कहा कि वहां के हिंदुओं को अकेले पड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया का हिंदू समाज उनके समर्थन में खड़ा है। मुंबई के नेहरू सेंटर में संघ के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित एक लेक्चर में भागवत जी ने कहा, बांग्लादेश में करीब सवा करोड़ (1.25 करोड़) हिंदू हैं। अगर वे वहीं रहकर अपने अधिकारों के लिए लड़ने का फैसला करते हैं तो दुनिया भर के सभी हिंदू उनकी मदद के लिए आगे आएंगे।पिछले कुछ समय से बांग्लादेश में अल्पसंज़्यकों, खासकर हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की घटनाएं बढ़ी हैं। यह सब अगस्त 2024 में शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद शुरू हुआ। इस तज़्तापलट के बाद बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हुए। इस उथल-पुथल के बीच हिंसक भीड़ ने हिंदू व्यापारियों, मजदूरों और छात्रों को निशाना बनाया। कई लोगों की जान गई और संपज़्तियों को नुकसान पहुंचाया गया। इसके बाद, छात्र नेताओं की मौत और राजनीतिक अस्थिरता के बाद ये हमले संगठित रूप से हिंदुओं के खिलाफ मुड़ गए।भागवत जी ने जोर देकर कहा कि ऐसी मुश्किल घड़ी में एकता ही सबसे बड़ा समाधान है। उन्होंने यह संदेश दिया कि बांग्लादेश के हिंदुओं को डरकर भागने के बजाय अपनी जगह सुरक्षित करने के लिए हिज़्मत जुटानी होगी और इसमें बाहरी दुनिया के हिंदू उनका साथ देंगे।

सेना प्रमुख ने आतंकवाद रोधी अभियानों की समीक्षा की, उन्नत तकनीकों के इस्तेमाल पर चर्चा की

नयी दिल्ली ०८/०२ (संवाददाता): भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने जज़्मू संभाग के रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सीमावर्ती जिलों, पुंछ और राजौरी का दौरा कर सुरक्षा स्थिति और आतंकवाद-रोधी अभियानों की गहन समीक्षा की। सेना द्वारा रविवार को दी गई जानकारी के अनुसार, इस दौरे का मुज़्य उद्देश्य मौजूदा सुरक्षा परिदृश्य का आकलन करना और आतंकवाद के खिलाफ सेना की संचालनात्मक क्षमता को और अधिक घातक बनाना था।

जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने यहां अग्रिम क्षेत्रों के दौरे पर आतंकवाद-रोधी अभियानों और मौजूदा सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की और इस दौरान संचालनात्मक क्षमता को और मजबूत करने के लिए उन्नत तकनीकों को शामिल करने पर भी चर्चा की गयी। सेना ने रविवार को यह जानकारी दी।

सेना प्रमुख ने शुक्रवार को गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित एक उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक में हिस्सा लिया था और जज़्मू में 'व्हाइट नाइट कोर' के मुज़्यालय का दौरा किया। इसके बाद उन्होंने शनिवार को सीमावर्ती जिलों पुंछ और राजौरी का दौरा किया।सेना के अतिरिक्त जनसंपर्क महा निदेशालय (एडीजीपीआई) ने 'एज़्स' पर एक पोस्ट में कहा, ''सेना प्रमुख ने व्हाइट नाइट कोर के अंतर्गत आने वाली आतंकवाद रोधी बल का दौरा किया, ताकि मौजूदा सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की जा सके और संचालनात्मक तैयारियों का आकलन किया जा सके।'

'उन्होंने क्षेत्र में जारी आतंकवाद-रोधी अभियानों, सुरक्षा व्यवस्था की प्रभावशीलता तथा लगातार सतर्कता बनाए रखने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी प्राप्त की। आतंकवाद रोधी बल (रोमियो) या सीआईएफ (आर) सेना की एक विशेष इकाई है, जो राजौरी और पुंछ जिलों के चुनौतीपूर्ण इलाकों में आतंकवादी नेटवर्क के खिलाफ अभियानों की जिज़्मेदारी संभालती है।एडीजीपीआई ने बताया, ''बातचीत में विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय बढ़ाने और संचालनात्मक क्षमता को और सुदृढ़ करने के लिए उन्नत तकनीकों के समावेश पर भी ध्यान केंद्रित किया गया।'' सेना ने कहा कि सेना प्रमुख ने सभी पद के जवानों की अटूट निष्ठा, पेशेवर रवैये और कर्तव्य के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता की सराहना की।

प्राइवेट चार्टर प्लेन क्रैश! इंजन फेल होने के बाद खेतों में करनी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग

विजयपुरा ०८/०२ (संवाददाता): कर्नाटक के विजयपुरा जिले से रविवार को एक बड़े विमान हादसे की खबर सामने आई है। रेडबर्ड एविएशन का एक छोटा ट्रेनिंग विमान तकनीकी खराबी के बाद बालेश्वर तालुक के मंगलुरु गांव में क्रैश हो गया। इस दुर्घटना में विमान के परखच्चे उड़ गए, लेकिन चमत्कारिक रूप से इसमें सवार दोनों पायलटों की जान बच गई।विमान ने कलबुर्गी से बेलगावी के लिए एक नियमित ट्रेनिंग उड़ान भरी थी। उड़ान के दौरान जब विमान मंगलुरु गांव के ऊपर था, तभी उसके इंजन में अचानक तकनीकी खराबी आ गई। कैप्टन और ट्रेनी पायलट ने हवा में ही इंजन को फिर से शुरू करने की कोशिश की, लेकिन इंजन पूरी तरह फेल हो गया। विमान तेजी से ऊंचाई खोने लगा और पायलटों को आबादी वाले इलाके से दूर एक खुले खेत में इमरजेंसी लैंडिंग करने का कठिन फैसला लेना पड़ा। चश्मदीदों के अनुसार, विमान को नीचे गिरते देखना एक खौफनाक मंजर था।

खराब हो रहे रेडबर्ड विमान में, कैप्टन और ट्रेनी ने खराब इंजन को ठीक करने की व्यर्थ कोशिश की, लेकिन उनकी सूझबूझ से शायद एक बड़ा हादसा टल गया। विमान इतनी तेज़ी से जमीन से टकराया कि दोनों यात्रियों को गंभीर चोटें आईं, फिर भी चमत्कारिक रूप से उनकी जान बच गई - इस घटना में कोई मौत नहीं हुई।

धूल और मलबा हवा में फैल गया, जैसे ही स्थानीय लोग मदद के लिए दौड़े, उनकी चीखें मुड़े हुए धातु की आवाज़ के साथ मिल गईं। कुछ ही मिनटों में, 108 एज़्बुलेंस घटनास्थल पर पहुंची, और खून से लथपथ पायलटों को गंभीर इलाज के लिए विजयपुरा के सबसे नज़दीकी अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉज़्टरों ने अफरा-तफरी के बीच उन्हें स्थिर किया।बालेश्वर पुलिस लगभग तुरंत ही दुर्घटनास्थल पर पहुंच गई, गांव में बिखरे मलबे को सुरक्षित किया और शुरुआती जांच शुरू की। जांच अधिकारी ने शुरुआती जानकारी देते हुए कहा, यह रेड बर्ड एविएशन का एक प्राइवेट विमान है। यह कलबुर्गी से बेलगावी जा रहा था, तभी इंजन में तकनीकी खराबी आ गई और अचानक क्रैश हो गया। विमान में दो लोग सवार थे, जिनकी पहचान कैप्टन और एक ट्रेनी पायलट के रूप में हुई है।

विविध समाचार

मलेशिया में पीएम मोदी का हुआ औपचारिक स्वागत, दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर

नयी दिल्ली०८/०२ (संवाददाता): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मलेशियाई समकक्ष अनवर इब्राहिम के साथ पेरडाना पुत्र बिल्डिंग में दोनों देशों के मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडलों से मुलाकात की और बातचीत की। प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत से पहले, रविवार को कुआलालंपुर में पेरडाना पुत्र बिल्डिंग में पीएम मोदी का औपचारिक स्वागत किया गया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया।

पीएम मोदी के शनिवार को कुआलालंपुर पहुंचने के बाद हुआ, जब मलेशियाई प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने हवाई अड्डे पर व्यक्तिगत रूप से उनका स्वागत किया। स्वागत के लिए मलेशिया के मानव संसाधन मंत्री रमणन रामकृष्णन और उप विदेश मंत्री लुकानिस्मान बिन अवांग सौनी भी मौजूद थे। आगमन समारोह में पारंपरिक संगीत और नृत्य प्रदर्शन के साथ रेड-कार्पेट स्वागत किया गया, जो भारत और मलेशिया के बीच साझा सांस्कृतिक विरासत का जश्न था। यात्रा के दूसरे दिन की शुरुआत सैन्य सज़्मान के साथ हुई। परदाना पुत्रा परिसर में आयोजित समारोह के मुज़्य अंशप्पीएम मोदी को मलेशियाई सशस्त्र बलों द्वारा (गार्ड ऑफ ऑनर) सलामी दी गई। समारोह स्थल पर पारंपरिक संगीत और नृत्य प्रस्तुतियों ने दोनों देशों की साझा विरासत और सांस्कृतिक जड़ों को प्रदर्शित किया।

गर्मजोशी भरे स्वागत पर प्रतिक्रिया देते हुए, पीएम मोदी ने ङ्ग पर पोस्ट किया- मेरे दोस्त, प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम द्वारा हवाई अड्डे पर किए गए गर्मजोशी भरे स्वागत से मैं बहुत प्रभावित हूं। मैं हमारी बातचीत और भारत और मलेशिया के बीच दोस्ती के बंधन को और मजबूत करने के लिए उत्सुक हूं।फ्न बाद में, दोनों प्रधानमंत्रियों ने एक ही वाहन में कुआलालंपुर में एक भारतीय समुदाय कार्यक्रम के स्थान तक यात्रा की, जिसमें पीएम अनवर इब्राहिम भी शामिल हुए। ङ्ग पर एक अपडेट साझा करते हुए, पीएम मोदी ने लिखा, भारत-मलेशिया के लोगों के बीच जुड़ाव का जश्न! पीएम अनवर इब्राहिम और मैं कुआलालंपुर में सामुदायिक कार्यक्रम में जा रहे हैं।

इन स्वागत कार्यक्रमों के बाद, पीएम मोदी और पीएम अनवर इब्राहिम रविवार, 8 फरवरी को व्यापक द्विपक्षीय चर्चा करने वाले हैं। उज़्मीद है कि बातचीत के परिणामस्वरूप विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से कई समझौते होंगे। यात्रा से पहले अपने प्रस्थान बयान में, पीएम मोदी ने जुड़ाव की प्राथमिकताओं पर प्रकाश डालकर माहौल तैयार किया था। उन्होंने कहा, भारत और मलेशिया के बीच ऐतिहासिक संबंधों में हाल के वर्षों में लगातार प्रगति हुई है। मैं प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ अपनी चर्चा और हमारी व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और बढ़ाने के लिए उत्सुक हूं। हम अपने रक्षा और सुरक्षा संबंधों को गहरा करने, अपनी आर्थिक और नवाचार साझेदारी को बढ़ाने और अपने सहयोग को नए क्षेत्रों में विस्तारित करने का लक्ष्य रखेंगे।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने यात्रा के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि इसमें एक समृद्ध एजेंडा है और यह भारत और मलेशिया के बीच विशेष साझेदारी को एक बड़ा बढ़ावा देगा। उन्होंने कहा, उज़्मीद है कि यह यात्रा हमारी घनिष्ठ और बहुआयामी साझेदारी को महत्वपूर्ण गति प्रदान करेगी। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मलेशिया की तीसरी यात्रा है और अगस्त 2024 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को कॉज़्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में अपग्रेड करने के बाद यह उनकी पहली यात्रा है। भारत और मलेशिया के बीच साझा इतिहास, सज़्यता और संस्कृति पर आधारित गहरे संबंध हैं। इन संबंधों को मलेशिया में रहने वाली लगभग 2.9 मिलियन भारतीय मूल की आबादी से और मज़बूती मिलती है, जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा प्रवासी भारतीय समुदाय है।

गौरव गोगोई का पाकिस्तानी कनेज़्शन! हिमंत बिस्वा सरमा के खुलासे से असम में भूचाल, जांच की मांग

गुवाहाटी ०८/०२ (संवाददाता): असम की राजनीति में इस वक्त एक बहुत बड़ा तूफान आया हुआ है। मुज़्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कांग्रेस नेता गौरव गोगोई और उनकी पत्नी एलिजाबेथ को लेकर कुछ ऐसे खुलासे किए हैं, जिन्होंने सबको चौंका दिया है। मामला %पाकिस्तानी कनेज़्शन% और नेशनल सिज़्योरिटी से जुड़ा है।

असम सरकार ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई थी जिसने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इस रिपोर्ट के आधार पर असम कैबिनेट ने अब भारत सरकार (रू्ञ्ज) से मांग की है कि इस मामले की जांच ह्लढ्ढ या ष्टक्चढ्ढ जैसी बड़ी केंद्रीय एजेंसियां करें।सीएम सरमा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि असम के एक बड़े नेता का पाकिस्तान से सीधा कनेज़्शन है। उनके मुज़्य आरोप ये हैं कि गौरव गोगोई अपने पिता तरुण गोगोई के सीएम रहते हुए पाकिस्तान गए थे, जिसकी जानकारी न तो पुलिस को थी और न ही केंद्र सरकार को।

सरमा का दावा है कि गौरव गोगोई पाकिस्तानी दूतावास भी गए थे, जो किसी भी कांग्रेसी नेता के लिए असामान्य है। साथ ही उनकी पत्नी एलिजाबेथ ने 2011-12 में पाकिस्तान में काम किया था और उनका सीधा संपर्क %अली तौकीर शेख% नाम के एक पाकिस्तानी एजेंट से था।

रिपोर्ट में एलिजाबेथ पर कई संगीन आरोप लगाए गए हैं, जिनमें कहा गया है कि 2013-14 में उन्होंने ढ्ढक्च (इंटेलिजेंस ज़्यूरो) की एक सीक्रेट रिपोर्ट की जानकारी पाकिस्तान को भेजी थी, ताकि वे भारत के खिलाफ अपनी रणनीति बदल सकें। साथ ही वे अज़्सर अटारी बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान जाती थीं और इन यात्राओं की कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी जाती थी। उन पर जॉर्ज सोरोस से जुड़े होने और विदेशी फंडिंग (स्नष्टक्र) के नियमों को तोड़ने का भी आरोप है। इसके साथ साथ ऐसा भी कहा गया कि उन्होंने अपने पाकिस्तानी बैंक खाते की जानकारी छिपाई।

इन आरोपों पर गौरव गोगोई ने पलटवार करते हुए इसे इस सदी की सबसे बड़ी ज़्लॉप प्रेस कॉन्फ्रेंस बताया है। उन्होंने कहा कि मुज़्यमंत्री की बातें किसी %ष्ट-ग्रेड फिल्म% की कहानी जैसी हैं और यह सब उनकी अपनी %समय परिवर्तन यात्रा% से ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है। गोगोई ने सीएम और उनके परिवार पर ही जमीन कज़्जाने के आरोप लगाए हैं।

असम सरकार का कहना है कि स्ढ्ढञ्ज की अपनी सीमाएं हैं ज़्योंकि इस मामले में इंटरपोल और संसद की सीक्रेट फाइलों तक पहुंच की जरूरत है। इसलिए अब गेंद केंद्र सरकार के पाले में है। गृह मंत्रालय (रू्ञ्ज) तय करेगा कि इस मामले की जांच आगे कौन सी एजेंसी करेगी।

एपस्टीन फाइल में दलाई लामा का नाम 169 बार, कार्यालय ने आरोपों को सिरे से किया खारिज

नयी दिल्ली ०८/०२ (संवाददाता): विवादित अमेरिकी फाइनेंसर और यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन से जुड़ी फाइलों में बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा का नाम आने के बाद पूरी दुनिया में चर्चा शुरू हो गई है। रविवार को दलाई लामा के ऑफिस ने एक आधिकारिक बयान जारी कर इन मीडिया रिपोर्ट्स का कड़ा खंडन किया। ऑफिस ने साफ तौर पर कहा कि दलाई लामा का एपस्टीन से किसी भी तरह का कोई संबंध नहीं रहा है।

हाल ही में अमेरिकी न्याय विभाग ने एपस्टीन केस से जुड़े लाखों दस्तावेज और वीडियो जारी किए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इन फाइलों में दलाई लामा का नाम कथित तौर पर 169 बार आया है।

कुछ फाइलों में %मसाज फॉर डमीज% नामक किताब और पुराने ईमेल के स्क्रीनशॉट मिले हैं, जिनमें दलाई लामा का जिक्र था। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि 2012 के आसपास उनके और एपस्टीन के बीच किसी मुलाकात की योजना बनाई गई थी।

इन दावों को पूरी तरह खारिज करते हुए दलाई लामा के ऑफिस ने बयान दिया। बयान के अनुसार, हम स्पष्ट करते हैं कि महामहिम दलाई लामा कभी भी जेफरी एपस्टीन से नहीं मिले हैं। न ही उन्होंने अपनी ओर से किसी व्यक्ति को उनसे मिलने या बात करने की अनुमति दी है। सोशल मीडिया और मीडिया में चल रही ये खबरें निराधार हैं।

यह मुद्दा पहली बार चर्चा में नहीं आया है। पिछले साल पत्रकार माइकल वोल्फ ने एक पॉडकास्ट में दावा किया था कि एपस्टीन के न्यूयॉर्क स्थित घर पर होने वाली सभाओं में कई दिग्गज शामिल होते थे, जिनमें उन्होंने दलाई लामा का भी नाम लिया था। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि अगर कोई संपर्क हुआ भी होगा, तो वह केवल परोपकारी कार्यों या दान के सिलसिले में हो सकता है, ज़्योंकि एपस्टीन कई बड़ी हस्तियों को आर्थिक मदद देने के लिए जाना जाता था।

यूपी की अर्थव्यवस्था को लगेंगे पंख... सीएम योगी आदित्यनाथ ने भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को बताया गेम चेंजर

लखनऊ ०८/०२ (संवाददाता): उज़र प्रदेश के मुज़्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारत और अमेरिका के बीच हुए द्विपक्षीय व्यापार समझौते का पुरजोर स्वागत किया है। शनिवार देर रात जारी एक आधिकारिक बयान में मुज़्यमंत्री ने इस समझौते को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल और दूरदर्शी नेतृत्वफ्न का प्रतिफल बताया। उन्होंने विश्वास जताया कि प्रस्तावित टैरिफ (शुल्क) रूपरेखा से उज़र प्रदेश की निर्यात-आधारित अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में मदद मिलेगी।एक आधिकारिक बयान में मुज़्यमंत्री ने कहा कि द्विपक्षीय व्यापार समझौते के तहत प्रस्तावित भारत-अमेरिका शुल्क (टैरिफ) रूपरेखा राज्य की निर्यात-आधारित अर्थव्यवस्था को उल्लेखनीय रूप से मजबूत करेगा। उन्होंने कहा कि इससे लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) और श्रम-प्रधान

उद्योगों को संरचनात्मक सहयोग मिलेगा तथा निवेश और रोजगार के दीर्घकालिक अवसर सृजित होंगे।ुज़्यमंत्री ने कहा कि यह रूपरेखा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मजबूत और दूरदर्शी नेतृत्व का परिणाम है और किसानों के हितों तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रक्षा करते हुए भारतीय निर्यातकों के लिए वैश्विक अवसरों का विस्तार करेगा।

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह पहल 'मेक इन इंडिया' को मजबूती देने के साथ-साथ महिलाओं और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी सृजित करेगी। उन्होंने इस समझौते को आगे बढ़ाने में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के प्रयासों की सराहना करते हुए उनका आभार भी व्यक्त किया।

मुज़्यमंत्री ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते के तहत जारी संयुक्त बयान ने उज़र प्रदेश की निर्यात-आधारित अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण नीतिगत संकेत दिया है। उन्होंने कहा कि इस समझौते का प्रभाव केवल व्यापारिक आंकड़ों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि कपड़ा उद्योग, लेदर, कृषि-आधारित उद्योग, एमएसएमई और औद्योगिक विनिर्माण जैसे उन क्षेत्रों पर भी पड़ेगा, जिनमें उज़र प्रदेश की भागीदारी राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख है।

योगी आदित्यनाथ ने कहा, ''वैश्विक स्तर पर हस्तनिर्मित कालीनों के लिए प्रज़्यात भदोही-मिर्जापुर कालीन निर्माण क्षेत्र लंबे समय से ऊंचे आयात शुल्क के कारण अमेरिकी बाजार में मूल्य प्रतिस्पर्धा की चुनौती झेल रहा था। शुल्क में कटौती के बाद इन उत्पादों की लागत संरचना में सुधार की संभावना है, जिससे निर्यात ऑर्डर और दीर्घकालिक आपूर्ति अनुबंधों को बढ़ावा मिल सकता है।'' उन्होंने कहा कि इसी तरह वाराणसी का रेशम और हैंडलूम क्षेत्र अमेरिकी बाजार में सीमित लेकिन स्थिर मांग के बीच बेहतर पहुंच हासिल कर सकता है। अमेरिका-भारत व्यापार समझौते में हैंडलूम क्षेत्र को शून्य शुल्क का लाभ मिलने की बात कही गई है। मुज़्यमंत्री ने क्षेत्रवार और विभिन्न कारोबार पर पड़ने वाले प्रभाव का उल्लेख करते हुए कहा कि शुल्क घटने से निर्यात श्रृंखला में उनकी सीधी भागीदारी बढ़ सकती है, जिससे मूल्यवर्धन का बड़ा हिस्सा स्थानीय स्तर पर ही बना रहेगा। बयान के अनुसार, योगी आदित्यनाथ ने कहा कि संयुक्त बयान में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कृषि, डेयरी, अनाज, मोटा अनाज, मसाले, पोल्ट्री जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में किसानों के हितों की सुरक्षा सर्वोपरि रहेगी। उन्होंने कहा कि उज़र प्रदेश जैसे कृषि-प्रधान राज्य के लिए यह प्रावधान विशेष महत्व रखता है, जहां बड़ी आबादी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से खेती, दुग्ध उत्पादन और पशुपालन पर निर्भर है।

सूरजकुंड मेला में टूटा झूला, बहादुर इंस्पेज़्टर की दर्दनाक मौत

फरीदाबाद ०८/०२ (संवाददाता): हरियाणा के पुलिस महानिदेशक अजय सिंघल ने शनिवार रात निरीक्षक जगदीश प्रसाद के निधन पर शोक व्यक्त किया। निरीक्षक प्रसाद शनिवार का सूरजकुंड मेला मैदान में झूला टूटने से हुए हादसे के दौरान लोगों को बचाने की कोशिश करते समय घायल होने के बाद निधन हो गया था। सिंघल ने मूलतः उज़र प्रदेश के मथुरा के रहने वाले निरीक्षक प्रसाद की मेले में ड्यूटी के दौरान उनकी असाधारण बहादुरी, समर्पण और मानवता के लिए सराहना की। उन्होंने जोर देकर कहा कि अत्यंत चुनौतीपूर्ण और जोखिम भरे हालातों के बावजूद, निरीक्षक प्रसाद ने अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों की सुरक्षा को सर्वोपरि रखा। सिंघल ने बताया कि अधिकारी की तत्परता और बहादुरी के कारण कई जीवन बचाए गए, जो पुलिस सेवा की सर्वोच्च परंपराओं को दर्शाता है। शनिवार को लगभग छह बजे, फरीदाबाद में सूरजकुंड मेले में एक झूला टूट कर गिर गया। उस समय ड्यूटी पर मौजूद निरीक्षक प्रसाद ने तुरंत बचाव कार्य शुरू किया।हालांकि, दूसरों की मदद करते समय उन्हें गंभीर चोटें लगीं और उपचार के दौरान उनका निधन हो गया। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, डीजीपी सिंघल ने घोषणा की कि निरीक्षक प्रसाद के परिवार को एक करोड़ रुपये की बीमा राशि के साथ अन्य विभागीय लाभ भी प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने भरोसा दिलाया कि हरियाणा पुलिस परिवार को हर संभव सहायता प्रदान करेगी।

गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने से सद्भाव बढ़ेगा

नयी दिल्ली ०८/०२ (संवाददाता): अखिल भारतीय मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रज़्वी बरेलवी ने मंगलवार को केंद्र और राज्य सरकारों से गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा देने से सामाजिक सद्भाव मजबूत होगा। इस्लामी दृष्टिकोण से उन्होंने कहा कि गाय के दूध में औषधीय गुण होते हैं और यह स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, जबकि गोमांस का सेवन बीमारी का कारण बन सकता है।

उज़र प्रदेश के मुज़्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने %गोदान% नामक फिल्म का पोस्टर जारी किया है। यह पोस्टर और यह फिल्म गायों से संबंधित है। इसमें संभवतः गायों के संरक्षण, सुरक्षा और बचाव से जुड़ी कहानियां हैं। मैं उज़र प्रदेश सरकार और भारत सरकार से गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग करता हूं। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने से कई समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। यदि आप इतिहास के पन्ने पलटेंगे, तो आपको गायों से जुड़े कई विवाद मिलेंगे। इसलिए, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के बाद ये समस्याएं समाप्त हो जाएंगी।

उन्होंने मुसलमानों को गाय का मांस न खाने और गाय पालन पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी ताकि उनके दूध से लाभ उठाया जा सके। उन्होंने आगे कहा कि मैं इस्लामी दृष्टिकोण प्रस्तुत करना चाहता हूँ। पैगंबर मुहज़्मद (उन पर शांति हो) की एक हदीस के अनुसार, गाय के मांस में रोग होता है और उसके दूध में शिफा (इलाज) होता है।

कलिंग समाचार
THE KALINGA SAMACHAR
(A Hindi Daily News Paper)
PUBLISHED FROM ODISHA, JHARKHAND & CHATTISHGARH
FOR NEWS AND ADVERTISEMENT CONTACT
AT: QRS. NO. B/204, SECTOR-16
ROURKELA, PH. 0661-2646999
PRAKASH KUMAR DHAL (EDITOR)
E-mail: thekalingasamachar@gmail.com

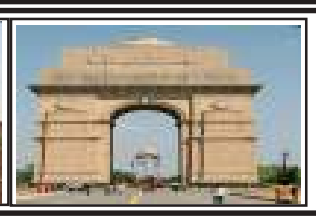

विविध समाचार

चारा फसल बरसीम लगायें

बरसीम

य इ एक बढ़िया किस्म की पौष्टिक प्रोटीनयुक्त चारा फसल है।

जलवायु

इसकी काश्त के लिए ठंडी से साधारण ठंडी जलवायु चाहिए। इस फसल की काश्त हेतु गर्म और उमस भरा वातावरण ठीक नहीं होता। जिस मिट्टी में कैल्शियम तथा फास्फोरस भरपूर मात्रा में मौजूद होता है तथा साधारण विम्लीय होती है और जिस मिट्टी से पानी की निकासी आसानी से होती है। यह उपयुक्त होती है।

बुआई का समय

उत्तर भारत में बरसीम की बुआई सितम्बर के मध्य से (यानि 15 सितम्बर से) अक्टूबर तक की जा सकती हैं। खेत में एक बार अच्छी जुताई कर दो से तीन बार बखर चलाये। खेत को समतल बनायें। खेत में सिंचाई कर मिट्टी में अंकुरण के लिए पर्याप्त नमी आने पर बरसीम का बीज खेत में बिखेर दें।

बुआई से पहले की तैयारी

बीजोपचार

बरसीम का बीज पानी में 10 से 12 घंटे तक भिगोये ताकि उसके ऊपर का छिलका थोड़ा नरम हो जायें और अंकुरण अच्छा हो। इसके बाद 100 ग्राम गुड 1 लीटर पानी में घोलकर उसे 5–10 मिनट तक उबालकर ठंडा करें और फिर उसमें 1 किलोग्राम जीवाणुसंवर्धक राइजोबियम मिलाकर धीरे–धीरे बीजों की सतह पर लगायें। सावधानी रखें कि बीजोपचार करते वक्त छिलकों को धक्का ना लगे। इस बीज को छाया में जमीन पर पतली परत में सुखायें और 24 घंटों के भीतर बुआई करें।

बीज मात्रा

सामान्यतः 25 से 30 किलोग्राम बीज एक हेक्टर क्षेत्र के लिए पर्याप्त होता है।

खाद मात्रा

बुआई से पहले प्रति हेक्टर भूमि में 25 टन अच्छी तरह सड़ी–गली स्यूमस युक्त खाद डालकर उसे बखर चलाकर अच्छी तरह मिट्टी में मिलायें। इसके अलावा 70–75 किलोग्राम फास्फोरस, 25 किलो नत्रजन तथा 40 किलो पोटाश मिट्टी में डालकर फिर सिंचाई कर दें।

सिंचाई

आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें ताकि पौधे अच्छी तरह जम जायें। शुरूआत में बुआई के 4–5 दिन के अंतराल से 2–3 बार हल्की सिंचाई करें। फुहार पद्धति के अंतराल से सिंचाई कर सकते हैं। अगर तापमान में वृद्धि हो और जमीन सूखी दिखे तो 10 दिनों बाद भी सिंचाई कर सकते हैं।

खरपतवार नियंत्रण

बीज में अक्सर अमरबेल (इसके पत्ते नहीं होते और इसका तना पीले रंग का होता है) के बीज का मिश्रण होता है। फसल के साथ यह भी बढ़ता हैं और फसल का पोषण चुरा लेता है जिससे फसल की बढ़वार और उत्पादन दोनों में कमी आती है। अतः इसे उखाड़कर जला दें। इसी प्रकार कासनी नामक खरपतवार का भी नाश करें।

चारे की कटाई

चारे की ऊंचाई 35 सेंटीमीटर तक पहुंच गई तो 40 से 45 दिन बाद ही पहली कटाई कर सकते हैं। पहली बार कटे चारे में 90 प्रतिशत नमी और सिर्फ 10 प्रतिशत शुष्क पदार्थ होता हैं। शुष्क पदार्थ की मात्रा हर कटाई के बाद 1.5 प्रतिशत बढ़ती है। पहली कटाई के बाद फसल की बढ़वार अनुसार 25 से 30 दिन के अंतराल से दूसरी कटाई कर सकते हैं। इसके बाद 30 दिनों के बाद तीसरी और चौथी कटाई कर सकते हैं। अंत में पांचवी और छटी कटाई 20 दिनों के अंतराल से कर सकते हैं। कटाई जमीन से 6 से 8 सेंटीमीटर ऊंचाई पर करें ताकि सिंचाई के बाद फसल फिर से बढ़े। कटाई, अपने पास कितने पशु हैं और कितनी जरुरत है इस हिसाब से करें।

उत्पादन

फसल की बढ़वार मिट्टी का प्रकार, उसमें मौजूद पोषक दव्य, सिंचाई आदि पर निर्भर होती है। औसतन 75 से 100 टन तक हरे चारे का उत्पादन की अपेक्षा की जा सकती है।

बरसीम में करीब 17.5 प्रतिशत कच्चा प्रोटीन तथा 2.5 से 2.6 प्रतिशत पाचनीय कच्चा प्रोटीन होता है। इसमें कैल्शियम ज्यादा और फास्फोरस कम होने से इसके साथ फास्फोरस से भरपूर गेहूं का भूसा खिलाना जरुरी होता है। इसके अंदर प्रोटीन ज्यादा होने से तथा खोखले डंठल होने से उसमें हवा रहती है। अतः ज्यादा खाने से पशु को आफरा की शिकायत हो जाती है। अतः सीमित मात्रा में ही पशु को खिलायें।

धनिया की उन्नत किस्में

भूमि

अ च्छे जल निकास वाली रेतीली दुमट या कटिबर दुमट भूमि जिसकी उत्तम उर्वराशक्ति हो उपयुक्त रहती है। क्षारीय एवं अम्लीय भूमि में उपज अच्छी प्राप्त नहीं होती। असिंचित क्षेत्रों के लिये भारी किस्म की भूमि जिसमें जल धारण क्षमता अच्छी हो, अधिक उपयुक्त होती है। सिंचित अवस्था में सभी प्रकार की भूमि जिसमें पर्याप्त जैविक अंश मौजूद हो धनिया की खेती की जा सकती है।

खेत की तैयारी

असिंचित खेती के लिये भूमि में सिंचित वर्षा की नमी जब उचित स्तर पर आ जाए खेत की तैयारी शुरू कर दें। पहली गहरी जुताई के पश्चात 2 से 3 जुताई देशी हल या हेरो से करके मिट्टी को भुरभुरा बना लें। जुताई के बाद पाटा अवश्य लगायें ताकि ढेले अच्छी तरह से फूट जायें। सिंचित फसल के लिये भूमि में अगर नमीं का अभाव हो तो पलेवा देकर खेत की तैयारी करें। हल्की मिटटी में कम एवं भारी मिटटी में अधिक जुताई की आवश्यकता होती है। ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करना लाभप्रद होता है।

उन्नत किस्में

गुजरात धनिया , गुजरात धनिया 2, को.1 को.2, को. 3, आर.सी.आर.41, आर.सी.आर.20, पूसा चयन 360, स्वाति, लाम चयन सी.एस. 2, साधना, राजेन्द्र स्वाति, सी.एस. 287, ग्वालियर नं.5365, सिन्दु, आर.सी.आर.435, आर.सी.आर. 436, आर.सी.आर.446।

खाद एवं उर्वरक

धनिया की अच्छी फसल के लिये 20 से 25 टन गोबर या कम्पोस्ट की खाद प्रति हेक्टेयर की दर से प्रथम जुताई के पूर्व खेत में बिखेर दें। इसके अतिरिक्त नत्रजन 60 कि.ग्रा. स्फुर 40 कि.ग्रा. एवं पोटाश 20 कि.ग्रा. प्रति हे. की अनुशंसा की गई।

बीज की मात्रा

बीज की मात्रा बुवाई विधि पर निर्भर करती है। छिटकवाँ विधि से बुवाई के लिये 22 से 25 कि.ग्रा. एवं पंक्तियों में बुवाई के लिये 12 से 15 किग्रा प्रति हे. बीज की आवश्यकता होती है।

खाद एवं उर्वरक देने की विधि

असिंचित क्षेत्रों में गोबर एवं कम्पोस्ट खाद की पूरी मात्रा खेत की पहली जुताई के समय समान रूप से फैलाकर मिटटी में मिलाएं एवं नत्रजन, स्फुर एवं पोटाश की पूरी मात्रा खेत की अंतिम जुताई के समय मिट्टी में मिला दें। सिंचित क्षेत्रों मे खेत की अंतिम जुताई के समय नत्रजन की आधी मात्रा के साथ स्फुर एवं पोटाश की मात्रा खेत में समान रूप से छिटकाकर आधार खाद के रूप में दे। नत्रजन की शेष मात्रा को दो बराबर मात्रा में बंटे के 30 से 40 दिन बाद खेत में अतिरिक्त पौधों को निकालने के पश्चात खडी फसल में बिखेर दें।

बुवाई का समय

धनिया मुख्यतः रबी की फसल है। अधिकांश क्षेत्रों में वर्षाधारित खेती की जाती है। इसलिये इसे शुद्ध या मिश्रित फसल के रूप मे उगाया जाता है। बुवाई के लिये सर्वोत्तम समय अक्टूबर से लेकर नवम्बर का द्वितीय सप्ताह होता है, क्योंकि इस समय ठंड अधिक नहीं पड़ती है। उत्तरी भारत में धनिये की बोआई का उपयुक्त समय 15 अक्टूबर से15 नवम्बर है।

बीजोपचार

मृदा एवं बीज जनित फफूंदी रोगों से बचाव हेतु धनिया के दानों को दो भागों में विभक्त करने के पश्चात थायरम , कार्बेन्डाजिम के 3 ग्राम सम मिश्रण या ट्राइकोडरमा विरडी या ट्राइकोडरमा हार्जीनिया 4 ग्राम प्रति किलो की दर से उपचारित कर बुवाई करें।

बुवाई का तरीका

सामान्य तौर पर धनिया की बुवाई दो विधियों से की जाती है।

छिटकवा विधि

इस विधि में कम समय में अधिक क्षेत्र की बुवाई सुगमता एवं शीघ्रता से की जा सकती है। इस विधि मे अधिक बीज की आवश्यकता होती है। साथ ही बीजों का वितरण समान रूप से नहीं होता है। परिणामस्वरूप अंतः शस्य क्रियायें पूर्णरूपेण नहीं हो पाती जिससे उपज कम मिलती है।

कतारों मे बुवाई

धनिया की बुवाई पंक्तियों में करना अधिक लाभप्रद होता है। बुवाई के लिये कतार से कतार की दूरी 25 से 30 से.मी. एवं पौधे से पौधे की दूरी 10 से 12 से.मी. रखनी चाहिए। कूड़ में बीज की गहराई 3 से 5 से.मी. तक होनी चाहिए। बीज अधिक को अधिक गहराई पर बोने से अंकुरण कम प्राप्त होता है।

सिंचाई एवं जल निकास

फसल के अंकुरण के बाद पहली सिंचाई एवं दूसरी सिंचाई फूल आने के समय एवं तीसरी सिंचाई दाने के बनते समय करनी चाहिए। सामान्यतः धनिया की फसल को अधिक सिंचाई की आवश्यकता नहीं होता है। मौसम एवं मिट्टी की दिशा को देखकर सिंचाई आवश्यकतानुसार करें। खेत में पानी का भराव न होने दे अन्यथा फसल के मरने की आशंका रहती है। यदि खेत में पानी भर जाय तो उसे तुरन्त निकालने की व्यवस्था करनी चाहिये।

निराई

गुड़ाई एवं खरपतवार नियंत्रण - धनिया की फसल के साथ कई खरपतवार भी उग आते है जो भूमि से नमी, पोषक तत्वों स्थान धूप आदि के लिये प्रतिस्पर्धा करते है जिसके कारण पौधों के विकास एवं बढ़वार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। खरपतवार नियंत्रण के लिये दो बार निंदाई-गुड़ाई करनी चाहिये। बुवाई के 30 से 45 दिन बाद एवं दूसरी पहली निराई गुड़ाई के 60 से 70 दिन बाद करें। पहली के समय अतिरिक्त अनावश्यक पौधों को निकालकर पौधों से पौधों की दूरी 10 से 12 से.मी. कर ले। यदि फसल बड़े क्षेत्र मे उगाई गई है तो अंकुरण के पूर्व पेन्डामिथालिन 1.0 कि.ग्रा. सक्रिय तत्व का प्रति हेक्टेयर की दर से नमीं की अवस्था में छिड़काव करें। इसके बाद बुवाई के 40 से 50 दिन बाद निराई - गुड़ाई करनी चाहिये।

कटाई एवं गहाई

फसल 90 से 100 दिन में पककर तैयार हो जाती है। जब फूल आना बंद हो जाये और बीजों के गुच्छों का रंग भूरा हो जाये तब फसल कटाई के लिये तैयार मानी जाती है। कटाई के बाद फसल को खलिहान में छाया में सुखाना चाहिये।

उपज

सिंचित क्षेत्रों में औसत उपज 12 से 18 क्विंटल एवं असिंचित क्षेत्रों 6 से 8 क्विंटल प्रति हेक्टयर प्राप्त होती है।

भंडारण

दानों को सुखाने के पश्चात बोरियों में या कोठियों में भरकर नमीं रहित स्थानों में भंडारित करना चाहिये।

शीत ऋतु में मुर्गियों की देखभाल

● शीतऋतु के आगमन से पहले मुर्गियों के बाड़े की मरम्मत करवायें. खिड़कियाँ तथा दरवाजे ठीक–ठाक हालत में होने चाहिए. यूं तो मुर्गीफार्म पर मुर्गियों के बाड़ों की बगलों पर डालियां लगी होती हैं. जहां से शाम तथा रात्रि में ठंडी बर्फीली हवाओं से बाड़े के भीतर का तापक्रम गिरता है.

● मुर्गियों से सर्वाधिक उत्पादन लेने हेतु 44 डिग्री से 75 डिग्री फैरनहीट (13 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड) तापक्रम आवश्यक होता हैं. अर्थात् उत्तर भारत में शीतऋतु में जब वातावरण का तापक्रम 13 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे चला जाता हैं तब अंडा उत्पादन पर विपरीत असर पड़ सकता हैं. ऐसी स्थिति में बचाव हेतु बाड़े की बगलों पर मोटे टाट (बारदान) से बने पर्दे इस तरह लगवायें ताकि ठंडी हवाओं के झोकों से मुर्गियों को बचाया जा सके.

● पर्दों की निचली जगह पर बाँस बांध दें ताकि वे तेज हवाओं से ना उड़े और मुर्गियों को ठंडी हवाएं ना लगें. इसके अलावा अंडा उत्पादन बरकरार रखने हेतु तथा मुर्गियों को ठंड से बचाने हेतु बाड़े में बिजली के बल्ब (लट्टू) लगाना जरूरी हैं. यह उजाला उन्हें दिन का प्रकाश का समय मिलाकर 16 घंटों तक मिलना जरूरी हैं तभी ये दाना अच्छी तरह चुगकर अंडा देती रहती हैं. व शीतऋतु में मुर्गियों को ज्यादा ठंडा जल ना पिलाये बल्कि गुनगुना पानी देना बेहतर होगा.

● शीतऋतु में मुर्गियों की भूख बढ़ जाती है अतः उनके दोने (फीड ट्रफ) हमेशा दाने (गैंश) से भरे होने चाहिए। साधारणतः एक संकर मुर्गी को रोजाना 110 से 140 ग्राम दाना जरूरी होता है। पर्याप्त मात्रा में दाना ना मिलने पर अंडों की तादाद तथा वजन में गिरावट आती हैं. अतः उनके पोषण पर समुचित ध्यान दें.

● डीप लीटर पद्धति में रखी मुर्गियों के बाड़े में जो भूसा (लिटर) जमीन पर बिछा होता है वह सूखा होना चाहिए। उस पर पानी रिस जाये तो तुरन्त गीला बिछावन (लिटर) हटाकर वहां सूखा बिछावन डाल दें अन्यथा: मुर्गियों को ठंड लग सकती है.

● मुर्गियों का रोजाना निरीक्षण करें. सुस्त मुर्गियों की पशुओं के डाक्टर द्वारा जांच करवाकर दवा दें.

● रोजाना सबेरे सूरज निकलने के बाद ही टाट (बारदान) के पर्दे ऊपर लपेटकर रखें तथा वायुवीजन होने दें.

● मुर्गीघर से मुर्गियों की बिचड़ी निरन्तर निकासी करें तथा वहाँ साफ–सफाई रखें इससे मुर्गियों का स्वास्थ्य ठीक–ठाक रहने में मदद मिलेगी।

कलिंग समाचार

संपादकीय

सोमवार 09 फरवरी 2026

मोदी- दोनों हाथों में लड्डू

जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा था कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव को रोकने के लिए चाहे जितने कठोर नियम बना ले, उन्हें लागू करना आसान नहीं होगा। और ऐसा ही हुआ भी। यूजीसी द्वारा जारी नए नियमों पर देश भर में सवाल और बवाल दोनों खड़े हुए और उसके बाद सीधे सुप्रीम कोर्ट में इसे रोकने के लिए याचिकाएं दायर हुई, जिन पर गुरुवार 29 जनवरी को महत्वपूर्ण सुनवाई भी हो गई। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर अस्थायी रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि पहले दृष्टिकोण से यह प्रतीत होता है कि इन नियमों की भाषा में स्पष्टता की कमी है, जिससे उनका गलत उपयोग हो सकता है। मु य न्यायाधीश सूर्यकांत ने चेतावनी दी कि ऐसे नियम समाज को विभाजित कर सकते हैं और परिसरों में अमेरिका की तरह नस्लीय विभाजन जैसी स्थिति पैदा कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन नियमों की जांच की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनका दुरुपयोग न हो। कोर्ट ने केंद्र सरकार से इन नियमों की समीक्षा करने को कहा और तब तक उनके लागू होने पर रोक जारी रखने का आदेश दिया। इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल से कहा कि वे एक विशेषज्ञ कमेटी गठित करें। जिसमें कुछ प्रतिष्ठित व्यक्तियों को शामिल करने पर विचार किया जाए, ताकि समाज में बिना भेदभाव के समग्र विकास हो सके। गौरतलब है कि यूजीसी नियमावली, 2026 को 13 जनवरी 2026 को अधिसूचित किया गया था। ये नियम अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) छात्रों के खिलाफ भेदभाव, उत्पीड़न और आत्महत्या जैसी घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से लाए गए हैं। यह 2012 के पुराने नियमों की जगह लाए गए हैं। इन नियमों के तहत सभी उच्च शिक्षा संस्थानों में समता समितियां (इक्विटी कमेटी) गठित करना अनिवार्य किया गया है। इस कमेटी का काम जातिगत भेदभाव की शिकायतों की जांच करना है। लेकिन एससी, एसटी और ओबीसी के हक की बात उठते ही समाज में बवाल खड़ा हो गया। भारत में जाति व्यवस्था इतनी गहरी पैठी हुई है कि जाति के नाम पर उत्पीड़न सामान्य व्यवहार के तौर पर अपना लिया गया है। एक इंसान दूसरे इंसान को केवल जाति के आधार पर अपमानित, शोषित या प्रताड़ित करे, यह चलन सदियों से चला आ रहा है और इसे दूर करने की जितनी कोशिशें की गईं, उतने ज्यादा अड़ंगे सवर्ण समाज की तरफ से लगाए गए। चाहे मंडल कमीशन की सिफारिशें हों या अभी यूजीसी के नए नियम, उन पर समाज का एक तबका ऐसे विरोध में उतरा मानो अपने से निचली जातियों का उत्पीड़न उसका जन्मसिद्ध अधिकार है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में सवर्ण वर्ग की ओर से दायर याचिकाओं में इन नियमों को असंवैधानिक बताया गया है। इसे जाति आधारित भेदभाव करार दिया। याचिकाकर्ताओं में से एक वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि यह भेदभाव संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 के खिलाफ है और इससे शिक्षा क्षेत्र में, समाज में और अधिक खाई पैदा हो सकती है। कितने कमाल की बात है कि शिक्षा क्षेत्र या समाज में जातिगत भेदभाव इन लोगों को तब दिखाई नहीं देता, जब किसी दलित बच्चों को मध्याह्न भोजन में अलग पंक्ति में बिठाने की खबरें आती हैं, या किसी छात्र को उसकी निचली जाति के कारण शारीरिक या मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया जाता है। रोहित वेमुला या पायल तड़वी जैसे लोगों को अगर आत्महत्या करने पर मजबूर किया गया, तो उसके पीछे यही सदियों से चला आ रहा जातिगत भेदभाव ही है। रसूखदार लोग बहरहाल, अब शीर्ष अदालत इस मामले पर अगली सुनवाई 19 मार्च को करेगी। तब तक मोदी सरकार जाति या किसी और कारण से समाज को बांटने के नए तरीके सोच ही लेगी। वैसे तो शिक्षा मंत्रालय और यूजीसी ने बचाव में कहा कि नए नियम किसी समुदाय को निशाना नहीं बनाते हैं और समितियां निष्पक्ष होंगी, जिसमें विविध प्रतिनिधित्व होगा।

बजट 2026-27 को वैश्विक उथल-पुथल के बीच स्थिर आर्थिक विकास का फ़ायदा

अंजन रॉय

यह सबसे नया मुक्त व्यापार समझौता खास तौर पर मुश्किल है। यह कम से कम दो दशकों से बन रहा था। फिर भी, अचानक यह जादू की तरह हो गया। सभी मुश्किल मुद्दे भुला दिए गए और समझौता हो गया। ऊपर से देखने पर, यह आर्थिक रणनीति के ठोस हिस्से के बजाय मु य रूप से एक राजनयिक उपकरण के तौर पर काम का लगता है। 2026-27 का भारतीय बजट अशांत माहौल के बीच आ रहा है। वैश्विक उथल-पुथल के बीच, भारतीय अर्थव्यवस्था खुशी-खुशी आगे बढ़ रही है। आखिर, हर साल ऐसा नहीं होता कि किसी वित्त मंत्री को बजट तैयार करने का मौका तब मिले जब अर्थव्यवस्था में गोल्डीलॉक्स का दौर हो, परी कथाओं की एक ऐसी नायिका का जो हर चीज को ठीक वैसा ही चाहती है जो उसके मनोनुकूल हो।

ताज़ा आंकड़े खुद ही सब कुछ बताते हैं= जीएसटी को आसान बनाने और त्योहारों पर होने वाले खर्च ने अक्टूबर-नवंबर के दौरान घरेलू मांग को बल दिया। ग्रामीण मांग मज़बूत बनी हुई है जबकि शहरी मांग में लगातार सुधार हो रहा है। निवेश की गतिविधि अच्छी बनी हुई है। निजी अंतिम उपभोक्ता खर्च (पीएफसीई) 2025-26 की दूसरी तिमाही में 7.9 प्रतिशत बढ़ा, जबकि 2025-26 की पहली तिमाही में यह 7.0 प्रतिशत था। सकल अचल पूंजी का सृजन (जीएफसीएफ) भी 2025-26 की दूसरी तिमाही में 7.3प्रतिशत पर मज़बूत बना रहा। द्यह्यश ऋद्धड्डस्र - मिशन-500 या कूटनीतिक आत्मसमर्पण? भारत-अमेरिका डील के अनकहे पहलू भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता था। भारत के एक के बाद एक वित्त मंत्री और आर्थिक प्रशासकों के लिए सबसे बड़ी चिंताओं में से एक कीमतों की स्थिति रही है। बेकाबू कीमतों ने वित्त मंत्रियों को अपने बजट तैयार करते समय परेशान किया था। महंगाई की रणनीति ने ही उनकी दक्षता और मेहनत को खत्म कर दिया। आर्थिक विकास की र .तार बनाए रखने के लिए तीन खास क्षेत्रों पर असरदार तरीके से काम करने की ज़रूरत है। पहला, घरेलू मांग को बढ़ावा देना और उसे बनाए रखना। दूसरा, वैश्विक अर्थव्यवस्था में मौजूदा उथल-पुथल को देखते हुए, जिसमें कई मुक्त व्यापार समझौते हो रहे हैं, वित्त मंत्री और वाणिज्य मंत्री को कस्टम ड्यूटी के ढांचे को सही बनाने और सुधारने के लिए मिलकर काम करना चाहिए।

तीसरा, कई प्रोत्साहनों के बावजूद, उद्योग और अर्थव्यवस्था के मूलभूत क्षेत्र (कोर सेक्टर) सुस्त साबित हो रहे हैं। पूरी अर्थव्यवस्था को तेज़ी से बढ़ने के लिए भारत के उद्योग क्षेत्र को दो अंकों के विकास दर के करीब होना चाहिए। इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। आइए इन पर थोड़ा विस्तार से बात करते हैं। अब, महंगाई कोई सिरदर्द नहीं रही — महंगाई के मौजूदा रास्ते एक बहुत बड़ा मौका देते हैं। अक्टूबर 2024 में शीर्ष पर जाने के बाद से, महंगाई में गिरावट आई है। पिछले कुछ महीनों से, यह रिज़र्व बैंक के सह्य सीमा 4प्रतिशत से कुछ नीचे है।

महंगाई में गिरावट के इस माहौल में, वित्त मंत्री खर्च बढ़ा सकती हैं। वह मांग बढ़ाने के लिए कई बड़ी परियोजनाएं शुरू कर सकती हैं। वह ज़्यादा निवेश को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से कम ब्याज दर की उ मीद कर सकती हैं।

असल में, अपने कैबिनेट साथी, नितिन गडकरी के साथ मिलकर, वित्त मंत्री, निर्मला सीतारमण, ज़्यादा बड़ी रोड बनाने का काम भी शुरू कर सकती हैं। रेलवे पहले से ही अपने हाई-स्पीड रेल नेटवर्क और रेल ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क में दूसरी चीज़ें जोड़ रहा है। ऐसी बड़ी परियोजनाएं और अवसंरचना बनाने से आज के मु य मैक्रो-इकानॉमिक मुद्दों में से एक का हल निकल सकता है— जैसे कि घरेलू मांग को बढ़ाने और रोज़गार पैदा करने के लिए अर्थव्यवस्था में ज़्यादा निवेश स्तर बनाए रखना। नए आंकड़े और वैश्विक अर्थव्यवस्था बताते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था को मज़बूत बनाए रखने के लिए घरेलू मांग सबसे अच्छा तरीका है। अनिश्चित वैश्विक हालात को देखते हुए, भारतीय अर्थव्यवस्था को घरेलू बाजार पर भरोसा करना चाहिए और विकास को बढ़ाने वाले मु य इंजन के तौर पर घरेलू मांग को बढ़ाने की रणनीति एक सुरक्षित दांव है। कर्ज के लिए कम ब्याज दर और आसान उपभोक्ता ऋ ण, पूंजी लाभ पर कर पर फिर से विचार और जमीन-जायदाद बाजार के आसान नियम और अवसंरचनात्मक विकास घरेलू मांग को बढ़ाने के लिए अहम हो सकते हैं। अगर घरेलू मांग अर्थव्यवस्था की र .तार को काफी तेज़ी से बढ़ा रही है, तो वैश्विक माहौल उथल-पुथल वाला है। भारत को अपने बाहरी आर्थिक रिश्तों के लिए अपने पूरे फ्रेमवर्क को नये सिरे से बनाना होगा। मुक्त व्यापार समझौता अब तेज़ी से हो रहे हैं, जिनमें सबसे नया यूरोपियन यूनियन के साथ है। यह सबसे नया मुक्त व्यापार समझौता खास तौर पर मुश्किल है। यह कम से कम दो दशकों से बन रहा था। फिर भी, अचानक यह जादू की तरह हो गया। सभी मुश्किल मुद्दे भुला दिए गए और समझौता हो गया। ऊपर से देखने पर, यह आर्थिक रणनीति के ठोस हिस्से के बजाय मु य रूप से एक राजनयिक उपकरण के तौर पर काम का लगता है। इसलिए, बजट में बाकी दुनिया के साथ भारत के रिश्तों को नये सिरे से बनाने में मदद के लिए कुछ ज़रूरी कदम उठाने चाहिए। यह एक बहुत बड़ी कोशिश साबित हो सकती है। एक तो, उत्पाद और उत्पादन श्रृंखला में उनकी जगह के हिसाब से टैरिफ के पूरे सेट की फिर से जांच होनी चाहिए। उत्पादन-उपभोग के गणित में उनकी जगह के हिसाब से वस्तुओं पर टैरिफ के ढांचे का गहराई से विश्लेषण किया जाना चाहिए। हमारे पास उल्टे टैरिफ के कई उदाहरण हैं— यानी, जिसमें अन्तिम उत्पादनों पर माध्यमिक उत्पादनों के मुकाबले कम टैरिफ लगते हैं। ये बाहर बने सामान के उपभोग को बढ़ावा देते हैं और देश में उसी के उत्पादन को हतोत्साहित करते हैं।

इन गड़बड़ियों को ठीक करने के लिए एक काम शुरू किया जाना चाहिए। बजट में भारतीय अर्थव्यवस्था की बड़ी कमजोरियों और कमियों पर भी ध्यान देना चाहिए। कई कोशिशों और प्रोत्साहनों के बावजूद, विनिर्माण उद्योग और मूलभूत क्षेत्रों के खिलाड़ी अभी भी पीछे हैं। औद्योगिक क्षेत्र ने उ मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं किया है। इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, खासकर उस महत्वाकांक्षी मुक्त व्यापार समझौते के संदर्भ में जिसे हम पूरा कर रहे हैं। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) में विकास अक्टूबर 2025 में 0.4 प्रतिशत तक कम हो गई, जो सितंबर 2025 में 4.6 प्रतिशत थी। स्टील की खपत और सीमेंट उत्पादन जैसे निर्माण संकेतकों में अक्टूबर के दौरान क्रमशः 2.4 प्रतिशत और 5.3 प्रतिशत की मामूली विकास दर दर्ज की गई। घरेलू औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने की ज़रूरत है। हाल के कुछ प्रोत्साहन कार्यक्रम भी औद्योगिक क्षेत्र के प्रदर्शन को बेहतर बनाने में ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए। अगर भारत को उच्च विकास दर की राह पर बने रहना है, तो उद्योग और विनिर्माण में दो अंकों की विकास दर ज़रूरी है। राज्य स्तर के सुधार और प्रदर्शन उद्योग की तेज़ विकास दर के लिए महत्वपूर्ण हैं और केंद्र सरकार को राज्यों के साथ मिलकर विस्तृत औद्योगिक विकास कार्यक्रम बनाने चाहिए। भारतीय उद्योग को अपने यूरोपीय समकक्षों के साथ मिलकर सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए और तालमेल से फायदा उठाने की योजना बनानी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम एक तरफ जितना फायदा उठाते हैं, उससे ज़्यादा दूसरी तरफ गंवा दें।

अर्थजगत का मायावी खेल हम चीन के साथ जाएं तब मुश्किल और अमेरिका से बंधे रहें तो और मुश्किल

अरविन्द मोहन

हम चीन के साथ जाएं तब मुश्किल और अमेरिका से बंधे रहें तो और मुश्किल। और इसी जुड़ाव की कीमत हमारा रुपया भी दे रहा है जो दुनिया की प्रमुख मुद्राओं के आगे डालर से भी ज्यादा तेजी से लुढ़क रहा है। मोदी जी भूल गए होंगे यह संभव नहीं लगता लेकिन हाल फिलहाल डालर कभी चालीस रुपए में मिलेगा इसकी संभावना तो दूर-दूर तक नहीं दिखती। ऐक्टिववियर यह आर्थिक मामलों में यथार्थ और माया के खेल को समझने का बहुत बढ़िया अवसर है और हम चाहें तो इसके लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्र प को धन्यवाद कह सकते हैं। वैसे वे खुद क्या हैं और आर्थिक मामलों में किस तीसरी चीज को हासिल करना चाहते हैं यह समझना मुश्किल है। वे तो क्रिप्टो करेंसी से लेकर और जाने किन चीजों के सौदागर हैं- खुद को शांति का सौदागर तो बताते ही हैं। आज जिस तरह शेयर बाजार, वित्तीय बाजार, करेंसी बाजार और बुलियन बाजार में अफरातफरी मची है वह बताती है कि वास्तविक अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य और काम काज से इनका बहुत कुछ लेना नहीं है। भारत ही दुनिया की आर्थिक गतिविधियों में कोई बड़ा उतार-चढ़ाव, खास तौर से गिरावट दिखाई नहीं देती लेकिन शेयर बाजार धड़ाम हो रहे हैं, करेंसी का उतार-चढ़ाव संभालने में सरकारों के पसीने छूट रहे हैं, निवेश बाजार से पूंजी निकालने और बाहर ले जाने की होड़ लगी है और बुलियन बाजार में आग लगी है। सोना-चांदी ही नहीं प्लेटिनम समेत सारे कीमती धातु रिकार्ड ऊंचाई पर हैं और मांग बढ़ती जा रही है। सोना और चांदी की कीमतें इस स्तर पर आ गई हैं कि आम आदमी के लिए इन्हें खरीदना मुश्किल है और जिनको सोने-चांदी से कोई लेना-देना नहीं रहा है वे किसी भी कीमत पर इनको खरीदकर जमा करते जा रहे हैं। और माया की तरह यह कहना भी आसान नहीं है कि इन गतिविधियों से अर्थव्यवस्था अप्रभावित है। उस पर भी खूब असर पड़ रहा है लेकिन खैरियत यही है कि महामंदी का कोई नया दौर आता नहीं दिखाता। पर मंदी कोई सूचना देकर थोड़े ही आती है। द्यह्यश ऋद्धड्डस्र - बजट- दूर-दूर तक नहीं दिखती विकास की राह यह माना जाता है की हमारा शेयर बाजार बहुत बड़ा नहीं है और इसमें देश-विदेश का जो पैसा लगा है उसमें काफी बड़े खिलाड़ी हैं। वे बाजार को कृत्रिम तरीकों से भी ऊंचा बनाए रखते हैं या सरकार में अपने ऊंचे रसूख से सरकारी बैंकों और बीमा तथा भविष्यनिधि समेत अन्य वित्तीय संस्थाओं से निवेश कराके बाजार को संभालते रहते हैं। वैसे यह सरकार की जवाबदेही भी है। इधर यह भी हुआ है कि विदेशी निवेशक बड़े पैमाने पर अपना निवेश वापस ले रहे हैं पर इधर देसी निवेश बढ़ाने से बाजार को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। लेकिन ट्र प महाराज के फैसले हंगामा मचाते रहे हैं और इस बार जब उन्होंने 500 फीसदी तक सीमा शुल्क बढ़ाने की बात उठाई तो सारे बाजारों का धीरज चूक गया।

धड़ाम हमारे बाजार भी हुए लेकिन इस बार बचाने का प्रयास करने वाले भी नदारद रहे। हमारी सरकार के दुलारे अदानी पर कार्रवाई की अमेरिकी पहल ने एक दिन में उनकी कई कंपनियों के शेयर में पंद्रह फीसदी तक की गिरावट ला दी। अकेले जनवरी में महीने में अब तक बाजार साढ़े चार फीसदी तक टूट चुका है और अब सभी बजट की ओर टकटकी लगाए बैठे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन कोई चमत्कार कर सकती हैं इसकी गुंजाइश कम ही लगती है।

भारत-अमेरिका डील के अनकहे पहलू सरकार और रिजर्व बैंक ने जब रुपए की गिरावट रोकने का प्रयास किया तब ज्यादा सफलता नहीं मिली। जनवरी भर में करीब 2.7 अरब डालर की विदेशी मुद्रा बाजार में उतार कर सरकार ने अपने दम भर प्रयास किया लेकिन वह सिर्फ गिरावट की र तार को कम कर सकी, गिरावट को रोकना संभव नहीं हुआ। डालर 91 रुपए के ऊपर पहुंचा तो यूरो 103 से ऊपर और पाउंड 125 के करीब। यह तब है जब रूस के तेल का भुगतान डालर में नहीं करना होता। डालर के उतार-चढ़ाव पर मोदी जी ने ही पहले काफी कुछ कहा है इसलिए ज्यादा कहने की जरूरत नहीं रहती। लेकिन मोदी सरकार इस तरह बेबस हो जाएगी, इसका कारण ट्र प की नीतियों की अनिश्चितता भर नहीं है। हमारी अर्थव्यवस्था में और आसपास के देशों की आर्थिक गतिविधियों में भी काफी कुछ बदल रहा है जो डालर को मजबूत बनाए न बनाए हमारे रुपए को कमजोर करता जा रहा है।

बाजार की तेजी का तो ट्र प की नीतियों या राजनीति से जितना नाता है हमारी सरकार की कमजोरी का भी वैसा ही नाता। सोने की कीमत प्रति दस ग्राम डेढ़ लाख के ऊपर पहुंचाने में हमारे आम लोगों का कोई हाथ नहीं है, %खास% अर्थात वायदा बाजार के खिलाड़ियों का भी बहुत योगदान नहीं है क्योंकि हमारे यहां सोने की कुल खरीद में काफी कमी आई है।

लेकिन चांदी की कीमत सवा तीन लाख प्रति किलो से ऊपर पहुंचाने में तो खिलाड़ियों की ही बड़ी भूमिका है। यह सही है कि चीन बड़े पैमाने पर चांदी खरीद कर वैश्विक तेजी का मु य खिलाड़ी बना हुआ है लेकिन हमारे वायदा बाजार के कायदे और खिलाड़ी भी कम बड़ी वजह नहीं हैं, खासकर इस कारण कि हमारे यहां चांदी की कोई कमी नहीं है और न कोई खास मांग आ गई है। यह शुद्ध सट्टेबाजी है और सरकार चुप बैठी है। वायदा बाजार में मार्जिन मनी बढ़ते ही तेजी और गिरावट का खेल यह बताता है कि मात्र दो फीसदी रकम से पचास गुना अधिक चांदी या मेटल को सट्टेबाजी में उलझा देने का खेल बड़े पैमाने पर हो रहा है। दुनिया के किसी भी बड़े वायदा कारोबार में इतने कम मार्जिन पर सौदे नहीं होते हैं। सोने चांदी के देखादेखी प्लेटिनम और दूसरी कीमती धातुओं के दाम भी रिकार्ड स्तर तक आ गए हैं। उत्पादक आर्थिक गतिविधियों की जगह अनुत्पादक चीजों के सहारे सट्टेबाजी का इससे बढ़िया उदाहरण शायद ही मिले। त्रासदी यह है कि लोग इसे ही सर्वाधिक सुरक्षित आर्थिक निवेश मान रहे हैं।

जिस अमेरिकी प्रतिभूतियों और डालर को कल तक सबसे सुरक्षित निवेश माना जाता था आज की यह हालत उनकी दुर्गति के चलते ही हुआ है। इसमें ट्र प का योगदान काफी बड़ा है लेकिन बीते कुछ समय से अमेरिकी आर्थिक प्रभुता में गिरावट के अन्य लक्षण भी दिखने लगे थे। हमारी मुश्किल यह है कि हम चीन के साथ जाएं तब मुश्किल और अमेरिका से बंधे रहें तो और मुश्किल। और इसी जुड़ाव की कीमत हमारा रुपया भी दे रहा है जो दुनिया की प्रमुख मुद्राओं के आगे डालर से भी ज्यादा तेजी से लुढ़क रहा है। मोदी जी भूल गए होंगे यह संभव नहीं लगता लेकिन हाल फिलहाल डालर कभी चालीस रुपए में मिलेगा इसकी संभावना तो दूर-दूर तक नहीं दिखती।

लोक शिक्षण के लिए समर्पित-पन्नालाल सुराणा

बाबा मायाराम

पन्नालाल सुराणा, सादगी, ईमानदारी, आदर्श की मिसाल थे। लिंगराज भाई ने बताया कि वे पूरे देश में घूम-घूमकर युवाओं को प्रशिक्षित करते रहते थे। इसके लिए लिखना और पढ़ना जीवनभर करते रहे। उन्होंने कुछ समय पत्रकारिता भी की और एक समाचार पत्र के संपादक भी थे। ऐसे लोगों से यह भी सीखा जा सकता है कि कार्यकर्ताओं का जीवन कैसा होना चाहिए। हाल ही में महाराष्ट्र के जाने-माने समाजवादी पन्नालाल सुराणा का निधन हो गया। वे 93 वर्ष के थे। वे एक ऐसे समर्पित व प्रतिबद्ध समाजवादी थे, जिन्होंने आदर्शवादी जीवन जिया। पूरे देश भर में घूम-घूमकर लोक शिक्षण करते रहे और कई किताबें भी लिखीं।

मुझे एक बार ही उन्हें सुनने का मौका मिला, जब हमारे कस्बे पिपरिया में आए थे। वहां एकलव्य संस्था के पुस्तकालय में एक छोटी गोष्ठी हुई थी, उसमें उनके विचार जानने को मिले। लेकिन मैं उनके बारे में कई लोगों से सुनता रहा हूं। पिछले कुछ महीनों से मैं ओडिशा के बरगढ़ शहर में हूं और यहां समता भवन में मेरा प्रवास है। यह समता भवन, प्र यात समाजवादी किशन पटनायक की याद में बना है। किशन पटनायक की पहल पर वर्ष 1995 में समाजवादी जन परिषद की स्थापना हुई थी, उससे भी पन्नालाल सुराणा जुड़े रहे हैं। वे राष्ट्र सेवा दल के भी पूर्व अध्यक्ष थे।

कल सामाजिक कार्यकर्ता लिंगराज भाई से पन्नालाल सुराणा के बारे में बात हो रही थी, तो उन्होंने बताया कि वे कई बार पन्नालाल सुराणा से मिले हैं। बैठकों और कार्यक्रम में साथ रहे हैं। उनके द्वारा लातूर भूकंप से पीड़ित बच्चों के लिए बनाए गए आपलां घर (अपना घर) में भी गए हैं। इस भूकंप में बड़ी सं या में लोग मारे गए थे और भारी तबाही हुई थी। सुराणा जी ने भूकंप पीड़ित बच्चों के लिए घर बनाया है, यहां बच्चों का शिक्षण व पालन-पोषण होता है। उन्होंने बताया कि वे आजादी आंदोलन के समय के बहुत ही समर्पित समाजवादी थे। किशन पटनायक, सुरेन्द्र मोहन, भाई वैद्य सभी एक ही पीढ़ी के थे। इन्होंने आजादी आंदोलन से लेकर जीवनपर्यंत तक देश को बनाने, युवाओं का शिक्षण करने और देश भर घूम-घूम कर लोगों को जगाने का काम किया। जीवन भर विचारों के लिए समर्पित रहे। वे बताते हैं कि किशन पटनायक के साथ वे कई बार महाराष्ट्र गए हैं और भाई वैद्य, जी.जी.पारिख, भाई वैद्य से मिलते रहे हैं। लिंगराज भाई बताते हैं कि महाराष्ट्र में सामाजिक कामों की ल बी परंपरा है। उन्होंने इस संदर्भ हाल ही समाजवादी दिवंगत जी.जी. पारिख को भी याद किया। जिन्होंने युसूफ मेहर अली केन्द्र के माध्यम से कई रचनात्मक काम किए।

विविध समाचार

डबल इंजन सरकार हरियाणा को विकास में अग्रणी राज्य बनाएगी : नायब सैनी

चंडीगढ़ ०८/०२ (संवाददाता): हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार प्रदेश को विकास के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है।

नव वर्ष में इस अभियान को और गति दी जाएगी तथा सरकार अंत्योदय के तीन मूल मंत्रों पर विशेष ध्यान केंद्रित करेगी। मुख्यमंत्री सैनी गुरुवार को चंडीगढ़ में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर सहकारिता एवं पर्यटन मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा भी उपस्थित रहे। सैनी ने बताया कि सरकार का पहला लक्ष्य महिला सशक्तिकरण है। दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। अब तक करीब आठ लाख महिलाओं को दो किस्तों में 250 करोड़ रुपये की राशि वितरित की जा चुकी है। उन्होंने पात्र महिलाओं से योजना में पंजीकरण कर लाभ उठाने का आह्वान किया।उन्होंने कहा कि दूसरा लक्ष्य युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराना है। इसके लिए 2026 तक का ड्रिवन रोडमैप तैयार किया गया है। गुरुग्राम और पंचकूला में हरियाणा एआई मिशन केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जहां युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स जैसी भविष्य की तकनीकों में प्रशिक्षित किया जाएगा। साथ ही पुलिस विभाग में 5500 कांस्टेबल पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि तीसरा लक्ष्य प्रकृति के अनुकूल खेती को बढ़ावा देना है। धान के स्थान पर वैकल्पिक फसलों की खेती को प्रोत्साहित किया जाएगा तथा एक लाख एकड़ भूमि को प्राकृतिक खेती के अंतर्गत लाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर को तेजी से पूरा करना भी सरकार की प्राथमिकता है। इस परियोजना से एनसीआर क्षेत्र में बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी, ट्रैफिक का दबाव कम होगा और औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने बताया कि क्षेत्रीय विकास और बुनियादी सुविधाओं में सुधार के उद्देश्य से कुंजपुरा (करनाल), मतलौडा (पानीपत) और शहजादपुर (अंबाला) को नगर पालिका का दर्जा दिया गया है। इस अवसर पर मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

'युद्ध नशे विरुद्ध' अभियान का दूसरा चरण, जालंधर में केजरीवाल और सीएम मान करेंगे शुरुआत

जालंधर ०८/०२ (संवाददाता): मान सरकार की मुहिम 'युद्ध नशे विरुद्ध' लगभग एक साल से जारी है। इसी कड़ी में आज जालंधर में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान इस अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत करेंगे। 'युद्ध नशे विरुद्ध' मुहिम के पहले चरण में बड़ी कार्रवाई करते हुए हजारों तस्करों की गिरफ्तारी, भारी मात्रा में नशीले पदार्थों की बरामदगी और करोड़ों रुपए की ड्रग मनी जब्त की गई है। सरकार का दावा है कि इस अभियान के जरिए पंजाब को नशा मुक्त बनाने की दिशा में निर्णायक कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार की इस मुहिम को प्रदेश में नशे के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी और संगठित कार्रवाई माना जा रहा है। मुख्यमंत्री मान के नेतृत्व में चल रहे इस अभियान का उद्देश्य

न सिर्फ नशा तस्करों पर शिकंजा कसना है, बल्कि युवाओं को नशे की गिरफ्त से बाहर निकालकर एक स्वस्थ और सुरक्षित भविष्य देना भी है। आज जालंधर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री भगवंत मान इस मुहिम के दूसरे चरण की औपचारिक शुरुआत करेंगे। सरकार के जारी आंकड़ों के अनुसार, इस मुहिम के पहले चरण में 1,859 किलो हेरोइन बरामद की गई, जोकि एक बड़ी उपलब्धि है। इसके साथ ही 43 हजार से अधिक नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, जिससे यह साफ होता है कि सरकार ने बड़े और छोटे सभी स्तर के अपराधियों पर कार्रवाई की है।

रूस में मृत युवक मनदीप के परिवार से मिले विधायक विक्रमजीत चौधरी, न्याय की मांग

गोराया। विधायक विक्रमजीत सिंह चौधरी ने रूस में दुखद परिस्थितियों में जान गंवाने वाले मनदीप कुमार के परिजनों से मुलाकात की। मनदीप के पिता अवतार चंद और भाई जगदीप से उन्होंने संवेदना व्यक्त की। मनदीप रोजगार की तलाश में विदेश गया था, जहां एजेंटों द्वारा धोखे से उसे रूसी सेना में भर्ती करा दिया गया, जिससे उसकी असमय मौत हो गई। हाल ही में मनदीप का पार्थिव शरीर भारत लाया गया है। मुलाकात के दौरान परिजनों ने अपना दर्द साझा करते हुए बताया कि पहले भी शिकायतें दी गई थीं, लेकिन अब तक संबंधित एजेंटों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। परिवार ने स्पष्ट किया कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलता, तब तक वे मनदीप का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। विधायक ने बताया कि उन्होंने मई 2024 में इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप के लिए विदेश मंत्रालय को पत्र लिखा था, लेकिन इसके बावजूद परिवार को अभी तक न्याय का इंतजार है। शोक संतप्त परिवार के साथ एकजुटता जताते हुए विधायक चौधरी ने कहा कि वे अब परिवार के साथ मिलकर गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय से संपर्क करेंगे। उन्होंने निष्पक्ष और समयबद्ध जांच, तुरंत एफआईआर दर्ज करने, सभी दोषी एजेंटों और मानव तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई तथा प्रशासनिक लापरवाही की जवाबदेही तय करने की मांग की। उन्होंने कहा कि यह मामला फर्जी विदेश नौकरी रैकेट के जरिए भारतीय युवाओं के शोषण की एक गंभीर और चिंताजनक तस्वीर पेश करता है, जो मानव तस्करी जैसा अपराध है। भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कड़े और त्वरित कदम उठाने की जरूरत है। विधायक ने कहा, "मनदीप कुमार को न्याय दिलाना सिर्फ एक परिवार की मांग नहीं, बल्कि राज्य की नैतिक जिम्मेदारी है।"

स्पेंड डीआईजी भुल्लर को राहत, सीबीआई कोर्ट ने दी जमानत

चंडीगढ ०८/०२ (संवाददाता): चंडीगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर सीबीआई कोर्ट के उस आदेश से है जिसमें CBI कोर्ट ने सस्पेंड DIG हरचरण सिंह भुल्लर को आय से अधिक संपत्ति के मामले में आज जमानत दे दी। कोर्ट ने यह फैसला इसलिए सुनाया क्योंकि सीबीआई तय समय 60 दिनों की अवधि के भीतर चार्जशीट दाखिल करने में नाकाम रही।

इस पर सीबीआई ने तर्क दिया कि ऐसे मामलों में 90 दिन का समय मिलता है। हालांकि रिश्वत से जुड़े एक अन्य मामले में वे फिलहाल जेल में रहेंगे। इससे पहले दो जनवरी को कोर्ट ने भुल्लर की जमानत अर्जी खारिज की थी। भुल्लर के वकील ने जमानत अर्जी में यही सवाल खड़ा किया था कि शिकायतकर्ता आकाश बत्ता से बिचौलिये ने सबसे पहले पांच अगस्त 2025 को एक लाख रुपये रिश्वत मांगी थी। जबकि उसने सीबीआई को 11 अक्टूबर 2025 को शिकायत दी। सीबीआई ने 16 अक्टूबर को निलंबित डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर को उनके मोहाली स्थित कार्यालय से गिरफ्तार किया था। इससे पहले उनके कथित बिचौलिए कृष्णु शारदा को भी हिरासत में लिया गया था। आरोप है कि दोनों ने मंडी गोबिंदगढ़ के स्क्रैप डीलर आकाश बत्ता से आठ लाख रुपये की रिश्वत मांगी थी।

पंजाब में आप सरपंच की गोली मारकर हत्या, मैरिज पैलेस में घुसकर बदमाशों ने की फायरिंग

अमृतसर। पंजाब के अमृतसर में आम आदमी पार्टी से जुड़े एक सरपंच की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान जरमल सिंह के रूप में हुई है, जो तरनतारन जिले के वल्टोहा गांव के मौजूदा सरपंच थे। वह परिवार के साथ एक शादी समारोह में शामिल होने आए थे, तभी बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार, शादी समारोह चल रहा था कि इसी दौरान दो अज्ञात युवक मैरिज पैलेस में दाखिल हुए और अचानक फायरिंग शुरू कर दी। हमलावरों ने सरपंच जरमल सिंह के सिर को निशाना बनाकर गोलियां चलाईं। गोली लगते ही वह गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल अवस्था में उन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया।

घटना के बाद समारोह स्थल पर अफरा–तफरी मच गई। फायरिंग की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मैरिज पैलेस को घेरकर जांच शुरू की। शादी में शामिल लोगों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस को आशंका है कि हमलावरों ने पहले से सरपंच की रेकी की हुई थी। पुलिस जांच में सामने आया है कि जरमल सिंह पर इससे पहले भी तीन बार हमले हो चुके थे। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और हमलावरों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है।

श्रम कानूनों को सबसे बड़ा आर्थिक सुधार, मजदूरों की मुश्किलें

चण्डीगढ़। भारतीय संसद से पास चार श्रम कानूनों को लागू करते हुए ऐसा ही दावा किया गया है। हैरानी की बात है कि अनेक मीडिया समूह भी अपने संपादकीय में इन कानूनों को इसी रूप में पेश कर रहे हैं। उनका कहना है कि यह भारतीय अर्थव्यवस्था के इतिहास में किसी भी केंद्र सरकार द्वारा किया गया सबसे बड़ा आर्थिक सुधार है। ध्यान रहे अब तक 1991 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव और उनके विज़ मंत्री मनमोहन सिंह की ओर से लागू किए गए उदारीकरण के फैसले को सबसे बड़ा आर्थिक सुधार माना जाता रहा है। अब उसकी जगह श्रम कानूनों को सबसे बड़ा आर्थिक सुधार बताया जा रहा है। लेकिन सवाल है कि ज़्या यह सबसे बड़ा कथित आर्थिक सुधार भारत की अर्थव्यवस्था को वैसे ही बदल पाएगा, जैसे 1991 के आर्थिक सुधारों ने बदला था? और ज़्या इससे श्रमिकों की हालत में कोई गुणात्मक परिवर्तन आएगा? इसकी संभावना कम है। बुनियादी रूप से ये चारों कानून कोई बड़ा बदलाव नहीं कर रहे हैं। इनकी जो एकमात्र बड़ी खासियत दिखाई दे रही है वह ये है कि पहले से मौजूद 29 केंद्रीय कानूनों को इन चार कानूनों में समेटा गया है। इस आधार पर दावा किया जा रहा है कि पहले इन 29 कानूनों की वजह से उद्योग व कारोबारी समूहों को इनके अनुपालन में समस्या आती थी तो दूसरी ओर श्रमिकों के लिए जरूरी लाभ उपलज़्ध कराना मुश्किल होता था। लेकिन असली सवाल तो यह है कि इससे मजदूरों को कैसे फायदा होगा? इस सवाल पर विचार से पहले चारों कानूनों के बारे में संक्षेप में जानना जरूरी है। ये चार कानून वेतन संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य व कार्य शर्तें संहिता हैं। पहला कानून यानी वेतन संहिता यह सुनिश्चित करेगा कि सभी मजदूरों को एक निश्चित वेतन मिले, वेतन समय पर मिले और वह उचित हो। पहले वेतन, भज़ा, पेंशन, बोनस आदि के लिए अलग अलग कानून थे, जिससे परेशानी होती थी। इसमें एक खास बात यह है कि महिलाओं को पुरुषों के समान काम के लिए समान वेतन का प्रावधान किया गया है। हालांकि उचित और समय पर वेतन मिलना कैसे सुनिश्चित होगा यह कानून लागू होने के बाद पता चलेगा। दूसरा कानून औद्योगिक संबंध संहिता हैं, जिसके तहत कर्मचारी और कंपनी के संबंधों की व्याज़्या की गई है और साथ ही दोनों के बीच विवाद के त्वरित निपटान की व्यवस्था भी बनाई गई है। इसमें हड़ताल और विरोध प्रदर्शन के नियम भी शामिल किए गए हैं और सबसे ज्यादा विरोध इसी नियम का हो रहा है। तीसरा कानून सामाजिक सुरक्षा संहिता का है, जिसमें असंगठित मजदूरों, ऐप आधारित सेवाओं में काम करने वाले लोग, जिन्हें गिग वर्कर्स कहा जा रहा है उनके लिए जरूरी प्रावधान किए गए हैं। इस कानून में कहा गया है कि कंपनियां इनके लिए सामाजिक सुरक्षा फंड बनाएंगी। इस कानून के जरिए स्वास्थ्य, बीमा और मातृत्व सुविधा जैसे लाभों को हासिल करना आसान बनाया जाएगा। चौथा और अंतिम कानून व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य व कार्य शर्तें संहिता है, जिसमें कर्मचारियों, मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रावधान है साथ ही कार्यस्थल पर होने वाली परेशानियों को दूर करके उसे बेहतर बनाने के उपाय भी किए गए हैं। पहले से मौजूद 13 कानूनों मिला कर इसे बनाया गया है। इसमें महिलाओं के रात में काम करने का प्रावधान भी किया गया है। दावा किया जा रहा है कि यह अद्भुत संतुलन वाला कानून है, जिससे मजदूरों और कर्मचारियों को भी फायदा होगा तो उद्योग समूहों को भी लाभ होगा। सवाल है कि जब दोनों के लिए फायदे वाला कानून है तो इसे लागू करने में सरकार को छह साल ज़्यों लग गए? दूसरा सवाल यह है कि अगर ये कानून मजदूरों के हित में हैं तो देश के ज्यादातर बड़े मजदूर संगठन इसका विरोध ज़्यों कर रहे हैं? असल में संसद में पास करने से लेकर इनके नियम बना कर इन्हें लागू करने तक जब भी इन कानूनों की बात होती है तो दावा किया जाता है कि इनसे मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा मिलेगी, स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा मिलेगी, समय पर व उचित वेतन मिलेगा तो दूसरी ओर कंपनियों को एक ऐसा सरल ढांचा मिलेगा, जिसके अनुपालन में उनको कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन यह सिर्फ सदिच्छा है। वास्तव में इसका कितना लाभ मिलता है यह इन कानूनों के अनुपालन के बाद पता चलेगा। परंतु उससे पहले इस कानून के कई प्रावधान ऐसे हैं, जिनको मजदूर फ्रेंडली कतई नहीं माना जा सकता है। उनसे ऐसा प्रतीत होता है कि मजदूरों को नियमों में बांधने, उनके विरोध करने की क्षमता को कम करने और उनकी नौकरी को असुरक्षित बनाने के प्रावधान इन कानूनों में निहित हैं। मिसाल के तौर पर औद्योगिक संबंध संहिता में प्रावधान किया गया है कि तीन सौ तक मजदूर और कर्मचारी वाला उद्योग सरकार की अनुमति के बगैर छंटनी कर सकता है। पहले एक सौ मजदूरों तक की कंपनियों को यह छूट मिली थी। यह दायरा बढ़ाने का मतलब है कि देश की ज्यादातर कंपनियां और उद्योग अपने यहां पहले से ज्यादा आसानी से छंटनी कर पाएंगे। इसमें लगभग पूरा एमएसएमई सेज़्टर आ जाता है। ध्यान रहे भारत में ज्यादातर कंपनियां इतने की मजदूरों या कर्मचारियों वाली हैं। इसका मतलब है कि सरकार ने ज्यादातर मजदूरों को कंपनियों की मर्जी के हवाले कर दिया है। इतना ही नहीं मजदूरों के हड़ताल या विरोध प्रदर्शन के अधिकार को भी सीमित कर दिया गया है। नए कानून में प्रावधान है कि हड़ताल से 60 दिन यानी दो महीने पहले नोटिस देना होगा। सोचें, अगर कर्मचारी या मजदूर अपनी किसी समस्या के लिए तत्काल विरोध प्रदर्शन या हड़ताल नहीं कर पाएंगे तो उनकी समस्या को निराकरण कैसे होगा? आवश्यक सेवाओं पर लागू होने वाले कानून को हर तरह के मजदूरों और कर्मचारियों पर लागू कर दिया गया है। इससे उनके विरोध प्रदर्शन को नियंत्रित करना आसान हो जाएगा। इतना ही नहीं कानून में यह भी प्रावधान किया गया है कि यूनियन की मान्यता पाने के लिए कंपनी के कुल कर्मचारियों की संज़्या के 10 फीसदी या एक सौ मजदूरों का, जो भी ज्यादा हो, उसमें शामिल होना जरूरी है। इससे छोटी यूनियन के समाप्त होने का खतरा है। सामाजिक सुरक्षा वाले तीसरे कानून में गिग वर्कर्स और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए सोशल सिज़्योरिटी फंड की बात कही गई है। लेकिन यह फंड कैसे बनेगा? कंपनियां कितना योगदान करेंगी और मजदूरों को उसका लाभ कैसे मिलेगा इस बारे में बहुत स्पष्टता नहीं है। इसी तरह व्यावसायिक सुरक्षा वाले चौथे कानून में रोज के काम के घंटे का विस्तार 12 घंटे तक कर दिया गया है। कंपनियां आठ से 12 घंटे काम करा सकेंगी।

Printed, Published,Edited, & Owned by Prakash Kumar Dhal, Printed at Promodini Publication, Main road , Chhend colony , Rourkela-15 & Published at ECR-73, Chhend Colony, Rourkela-15, Editor : Prakash kumar Dhal, Email:kalingasamachar@gmail.com , Mob: 9439951525, Ph. 0661-2646999

ओडिशा समाचार

कलिंग समाचार | राउरकेला, सोमवार 09 फरवरी 2026 | पृष्ठ-6

कोरापुट जिले में प्रशासनिक रिक्तियों से शिक्षा प्रभावित

कोरापुट ०८/०२ (संवाददाता): शिक्षा अधिकारियों की भारी कमी ने कोरापुट जिले में स्कूल शिक्षा प्रणाली में गंभीर प्रशासनिक कमियों को उजागर किया है, जिसमें अकेले नंदपुर ज्लॉक में एक ही असिस्टेंट ज्लॉक एजुकेशन ऑफिसर लगभग 200 संस्थानों की देखरेख कर रहा है। अकेली महिला क्ष्वह फिलहाल नंदपुर ज्लॉक की 23 पंचायतों में फैले 197 शैक्षणिक संस्थानों की जिज़्मेदारी संभाल रही है, जिनमें 16,000 से ज़्यादा छात्र पढ़ते हैं। इन संस्थानों में 137 प्राइमरी स्कूल, 34 अपर प्राइमरी स्कूल, 21 हाई स्कूल, पांच हायर सेकेंडरी स्कूल और एक ओडिशा आदर्श विद्यालय शामिल हैं।

ज़्लॉक रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर के तौर पर, यह अधिकारी 13 ज़्लस्टर की देखरेख करती है, 700 से ज़्यादा शिक्षकों पर नज़र रखती है, 190 स्कूलों में मिड-डे मील संचालन की निगरानी करती है, स्कूलों का निरीक्षण करती है और विभागीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों, बैठकों और अन्य प्रशासनिक जिज़्मेदारियों का प्रबंधन करती है। यह स्थिति कोरापुट जिले में कर्मचारियों की कमी के व्यापक संकट को दर्शाती है, जिसमें 14 ज़्लॉक हैं। इनमें से केवल छह ज़्लॉकों में नियमित ज़्लॉक एजुकेशन ऑफिसर हैं, जबकि बाकी आठ ज़्लॉक अतिरिक्त प्रभार वाले अधिकारियों द्वारा चलाए जा रहे हैं। हालांकि हर ज़्लॉक में तीन क्ष्वह नियुक्त करने का प्रावधान है — पूरे जिले में कुल 42 — लेकिन वर्तमान में केवल 17 ABEO ही पद पर हैं, जिससे 25 पद खाली हैं। कई मामलों में, अपर प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूलों के लेवल-ढ्ङ्क हेडमास्टरों को उनके नियमित शिक्षण कर्तव्यों के अलावा क्ष्वह की जिज़्मेदारियां भी सौंपी गई हैं। इनमें शैक्षणिक निर्देश, स्ष्ठरू की देखरेख, स्कूल की निगरानी और विभागीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों का समन्वय शामिल है। शिक्षाविदों ने चेतावनी दी है कि ऐसी दोहरी जिज़्मेदारियां जिले में शिक्षा विभाग की कमजोर और कर्मचारियों की कमी वाली स्थिति को उजागर करती हैं। यह समस्या मई 2025 से और बढ़ गई है, जब तत्कालीन नंदपुर क्ष्वह भवानी नंदन पटनायक का तबादला सेमिलिगुडा ज़्लॉक में कर दिया गया था। तब से कोई पूर्णकालिक प्रतिस्थापन नियुक्त नहीं किया गया है, और पटनायक को अतिरिक्त प्रभार संभालने के लिए कहा गया है।

नंदपुर में स्वीकृत तीन पदों में से दो भी खाली हैं, अप्रैल 2025 में एक सेवानिवृज़ि और हाल ही में एक और तबादले के बाद, जिससे पूरा प्रशासनिक बोझ क्ष्वह ममताज गोमांग पर आ गया है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत 4 फरवरी से टीचर ट्रेनिंग शुरू होने और जनगणना और पंचायत चुनावों से जुड़ी आने वाली ज़िज़्मेदारियों को देखते हुए, शिक्षा विशेषज्ञों को डर है कि स्टाफ की भारी कमी से ज़्लासरूम टीचिंग, स्कूल मैनेजमेंट, ट्रेनिंग शेड्यूल और स्ष्ठरू (मिड-डे मील) लागू करने पर बुरा असर पड़ेगा। ज़िला शिक्षा कार्यालय के सूत्रों ने बताया कि आठ ज़्लॉक — नंदपुर, बंधुगांव, बोरिगुज़्मा, दसमंतपुर, कोरापुट, नारायणपटना, लक्ष्मीपुर और पोट्टांगी — में अभी क्ष्वह (ज़्लॉक एजुकेशन ऑफिसर) के पद खाली हैं। रोज़ाना के कामकाज को संभालने के लिए, तीन अतिरिक्त ज़िला शिक्षा अधिकारियों (ष्ठश्वहह्य), पड़ोसी ज़्लॉकों के तीन क्ष्वह और हाई स्कूलों की दो हेडमिस्ट्रेस को दोहरा चार्ज दिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि स्टाफ की कमी और ज़रूरी ज़रूरतों के बारे में ज़िला कलेज़्टर और राज्य के स्कूल और जन शिक्षा (स्रूरूस्ब्) विभाग को औपचारिक रूप से बता दिया गया है। स्थानीय शिक्षाविदों, माता-पिता और सिविल सोसाइटी के सदस्यों ने उज़्मीद जताई है कि राज्य सरकार इस संकट से निपटने के लिए तुरंत कदम उठाएगी, खासकर इसलिए ज़्योंकि स्कूल और जन शिक्षा मंत्री अविभाजित कोरापुट ज़िले से हैं।

सेल द्वारा जनवरी'26 में अब तक का सर्वाधिक और अप्रैल-जनवरी वित्त वर्ष 2025-26 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दर्ज

राउरकेला ०८/०२ (संवाददाता): स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल), एक महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (ष्टक्कस्श्व) तथा देश की प्रमुख इस्पात उत्पादक कंपनियों में से एक, ने नए कीर्तिमान स्थापित करते हुए अप्रैल-जनवरी विज़ वर्ष 2025-26 की अवधि के दौरान कुल विक्रेय में 16त्न की वृद्धि हासिल की है। इस अवधि में कुल बिक्री 16.6 मिलियन टन (एमटी) रही, जो पिछले वर्ष की समान अवधि (सीपीएलवाई) के 14.3 एमटी की तुलना में अधिक है। यह कंपनी द्वारा अब तक दर्ज की गई सर्वाधिक संचयी बिक्री है।सेल ने जनवरी'26 में भी अब तक की सर्वश्रेष्ठ मासिक बिक्री दर्ज की, जो 1.84 एमटी रही, जबकि पिछले वर्ष की समान अवधि में यह 1.68 एमटी थी-यानी 10त्न से अधिक की वृद्धि। इसके परिणामस्वरूप भंडार (इन्वेंटरी) में 0.25 एमटी की कमी आई तथा उधार (बोरोइंग्स) में भी उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई।

इन अवधियों के दौरान दर्ज की गई रिकॉर्ड तोड़ उपलज़्धियाँ बिक्री, प्रेषण, नकद संग्रह और ग्राहक के द्वार तक आपूर्ति जैसे अनेक मापदंडों में परिलक्षित होती हैं। कंपनी ने संयंत्रों से रिकॉर्ड प्रेषण हासिल किया, घर-घर डिलीवरी की मात्रा में विस्तार किया और गोदामों में बिक्री को बढ़ाया, जो बाजार में अपनी पैठ को मजबूत करते हुए ग्राहक-केंद्रितता और लॉजिस्टिज़्स दक्षता पर ख़ास ध्यान देते हुए बाजार में पैठ को और गहरा करने को दर्शाता है।

मार्केटिंग वर्टिकल की पहलों से प्रेरित ये उपलज़्धियाँ परिचालन उत्कृष्टता को ग्राहक-केंद्रित रणनीतियों के साथ जोड़ने की सेल की क्षमता को रेखांकित करती हैं। निरंतर पूर्व रिकॉर्ड्स को पार करते हुए और व्यवसाय योजना के लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए, सेल भारत की विकास गाथा में एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में अपनी स्थिति को और सुदृढ़ करता जा रहा है।

सोलर शील्ड ने ग्रामीणों को खेतों में लौटने की शक्ति दी

ढेंकनाल ०८/०२ (संवाददाता): लगभग एक एकड़ ज़मीन का मालिक होने के बावजूद, निरंजन नायक ने 20 से ज़्यादा सालों से अपने खेत में खेती नहीं की थी। हर सुबह, वह अपने परिवार के दूसरे सदस्यों और गाँव वालों के साथ पास की पत्थर तोड़ने वाली यूनिट में दिहाड़ी मज़दूर के तौर पर काम करने जाता था। जिन दिनों यूनिट बंद रहती थी, वह मज़दूरी के लिए दूसरी जगहों पर जाता था, खासकर कंस्ट्रज़्शन साइट्स पर। यह ढेंकनाल ज़िले के सोरत गाँव की कहानी थी। गाँव के चारों ओर की विशाल ज़मीन, दो-तीन दशक पहले, धान, दालों से लेकर सज़्ज़ियों तक की हरी-भरी फसलों से भरी रहती थी। लेकिन फिर धीरे-धीरे, उपजाऊ खेत बंजर हो गए। सूखा, बाढ़ या कर्ज़ की वजह से नहीं, बल्कि इंसान और जानवरों के बीच बढ़ते टकराव के कारण। 2000 के दशक की शुरुआत तक सोरत के आसपास की खेती की ज़मीन झाड़ियों और जंगली पौधों से ढकने लगी, एक बड़ा हिस्सा तो बंजर और फटा हुआ रह गया, ज़्योंकि परिवारों को खेती छोड़कर बाहर काम ढूंढना पड़ा।

हमारा गाँव घने जंगल के पास है। साल-दर-साल, जंगली सूअर, बंदर, भौंकने वाले हिरण और हाथी हमारी ज़मीनों पर हमला करते थे और फसलों को बर्बाद कर देते थे। हमारे गाँव वाले दिन-रात खेतों की रखवाली करते थे, लेकिन समय के साथ हमले तेज़ होने से नुकसान बढ़ता गया। धीरे-धीरे, हमें खेती बंद करनी पड़ी ज़्योंकि हमारा जीवन खतरे में था।

बारीपदा में मेघासनी महोत्सव धूमधाम से शुरू हुआ

बारीपदा ०८/०२ (संवाददाता): यहां छौपड़िया में स्वदेशी और सुभद्रा शक्ति मेले के साथ मेघासनी महोत्सव-2026 शुरू होने के बाद बारीपदा शहर जश्न में डूब गया है। ये कार्यक्रम 12 फरवरी तक चलेंगे।मुज़्य अतिथि के तौर पर इस मौके पर मौजूद राज्यसभा सांसद ममता मोहंता ने कहा कि सुभद्रा योजना के तहत महिला लाभार्थियों को दी गई विज़ीय सहायता ने उन्हें एक नई पहचान दी है। सभा को संबोधित करते हुए जिला कलेज़्टर हेमाकांत साय ने कहा कि यह महोत्सव %एक जिला, एक उत्पाद% की अवधारणा को बढ़ावा देता है।

मेले का उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए ब्रांडिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग है। सुभद्रा शक्ति मेले में महिलाएं सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता की अपनी कहानियों को साझा करने के लिए आगे आएंगी।

ओडिशा हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को नेशनल ग्रीन ट्रिज़्यूनल से संपर्क करने का निर्देश दिया

कटक ०८/०२ (संवाददाता):ओडिशा हाई कोर्ट ने झारसुगुड़ा जिले में नेशनल हाईवे नंबर 49 के निर्माण के दौरान ज़्लाई ऐश को बिना किसी नियम के डंप करने से होने वाले पर्यावरणीय नुकसान के आरोप वाली एक रिट याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया और याचिकाकर्ताओं को नेशनल ग्रीन ट्रिज़्यूनल (ह्लत्रञ्ज) के सामने समाधान खोजने का निर्देश दिया। चीफ जस्टिस हरीश टंडन और जस्टिस एमएस रमन की डिवीजन बेंच सुमंता स्वैन और आठ अन्य लोगों द्वारा दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में ज़्लाई ऐश को अंधाधुंध तरीके से डंप करने के कारण हवा और पानी के प्रदूषण पर गंभीर चिंता जताई गई थी, जिससे याचिकाकर्ताओं के अनुसार, फसलों को नुकसान हुआ, तालाब और भूजल दूषित हुआ, मछलियां मरीं, और आस-पास के गांवों में सिंचाई और मछली पालन प्रभावित हुआ।बेंच ने शुरू में ही सवाल किया कि याचिकाकर्ताओं को नेशनल ग्रीन ट्रिज़्यूनल एज़्ट, 2010 के तहत उपलज़्ध कानूनी उपाय का इस्तेमाल करने का निर्देश ज़्यों नहीं दिया जाना चाहिए। आरोपों की गंभीरता को स्वीकार करते हुए, कोर्ट ने ऐसे मामलों में न्यायिक अनुशासन पर जोर दिया जहां विशेष फोरम मौजूद हैं। बेंच ने कहा, इस रिट याचिका में उठाए गए महत्वपूर्ण मुद्दे ज़्लाई ऐश को बिना किसी नियम के डंप करने से पर्यावरण में प्रदूषण और आस-पास के लोगों की फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान से संबंधित हैं, साथ ही सिंचाई और मछली पालन के लिए इस्तेमाल होने वाले तालाबों और भूजल के दूषित होने का भी जिक्र किया।

कांस्टेबल ने शादी का झांसा देकर महिला को धोखा दिया

केंद्रपाड़ा ०८/०२ (संवाददाता): एक 30 साल के पुलिस कांस्टेबल को शनिवार को शादी का झांसा देकर एक महिला का एक साल से ज़्यादा समय तक यौन शोषण करने के आरोप में गिरज़्तार किया गया।

आरोपी का नाम श्रुतिरंजन खुंटिया है, जो तांतियापाला मरीन पुलिस स्टेशन में कांस्टेबल है। 23 साल की शिकायतकर्ता के अनुसार, खुंटिया ने शादी का वादा करके पिछले एक साल में कई बार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, और जब उसने उस पर शादी करने का दबाव डाला, तो उसने कथित तौर पर उसे धमकी देना शुरू कर दिया।

पुलिस ने बताया कि बाद में शिकायतकर्ता को पता चला कि खुंटिया शादीशुदा है और उसका फायदा उठा रहा है। उसकी शिकायत पर कार्रवाई करते हुए, पुलिस ने आरोपी को ब्क्रहस् की संबंधित धाराओं के तहत गिरज़्तार किया।केंद्रपाड़ा टाउन ढ्ढढ्ढष्ट दिलीप साहू ने कहा कि खुंटिया को कोर्ट में पेश किया गया और उसकी जमानत याचिका खारिज होने के बाद उसे जेल भेज दिया गया। उन्होंने कहा, शिकायतकर्ता का केंद्रपाड़ा जिला मुज़्यालय अस्पताल में मेडिकल जांच की गई और उसके बयान दर्ज किए गए हैं।

पांच एकड़ में लगी अफीम की फसल नष्ट कर दी गई

टेन्सा ०८/०२ (संवाददाता): पुलिस और एज़्साइज अधिकारियों ने सुंदरगढ़ जिले के कोइडा इलाके में 30 लाख रुपये से ज़्यादा के अफीम के पौधे नष्ट कर दिए और अवैध खेती के सिलसिले में दो लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस के मुताबिक, कोइडा पुलिस स्टेशन इलाके के तहत गतापूंढी पोखरी जंगल क्षेत्र के पास करीब पांच एकड़ जंगल की ज़मीन पर अफीम की खेती की जा रही थी। पौधे पूरी तरह से बढ़ गए थे और उनमें फूल आने लगे थे। एक सूचना के आधार पर, राउरकेला स्क्र नितेश वधवानी के निर्देश पर यह ऑपरेशन किया गया। इस रेड का नेतृत्व कोइडा PS OIC राजेंद्र स्वैन, के बालंग OIC अशोक बेहरा, एज़्साइज अधिकारियों और कोइडा तहसीलदार निर्मल कुमार बिस्वाल ने किया। पुलिस ने बताया कि शुरुआती जांच से पता चला है कि इस अवैध खेती के तार ओडिशा से बाहर पश्चिम बंगाल और झारखंड तक फैले हुए हैं। पुलिस ने बताया कि हिरासत में लिए गए दोनों लोगों से पूछताछ की जा रही है और आगे की जांच जारी है।

रोल शॉप-४में 5एस के कार्यान्वयन से दक्षता, सुरक्षा और लागत बचत में वृद्धि

राउरकेला ०८/०२ (संवाददाता): राउरकेला इस्पात संयंत्र (आरएसपी) के रोल शॉप-४ में 'विजन' क्वालिटी सर्कल द्वारा 5एस कार्यस्थल प्रबंधन प्रणाली के व्यवस्थित कार्यान्वयन से परिचालन दक्षता, सुरक्षा तथा लागत बचत में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, जो आरएसपी की दक्षता और सतत सुधार पर केंद्रित प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

उल्लेखनीय है कि रोल शॉप-ढ्ढङ्क, नए प्लेट मिल को रोल असेंबली एवं शियर ज़्लेड की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 5एस के कार्यान्वयन से पूर्व शॉप में कमजोर हाउसकीपिंग, अव्यवस्थित भंडारण, स्थान का अप्रभावी उपयोग, सामग्री की खोज में अधिक समय तथा संभावित सुरक्षा जोखिम जैसी चुनौतियाँ थीं। इन समस्याओं के समाधान हेतु विजन क्वालिटी सर्कल टीम ने 5एस की संरचित पद्धति अपनाई, जिसमें सेइरी (पुनर्गठन), सेइतोन (व्यवस्थितता), सेइसो (सफाई), सेइकेत्सु (मानकीकरण) और शित्सुके (अनुशासन) शामिल हैं।

इस कार्यान्वयन को समर्पित समितियों, कर्मचारियों के प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रमों, आधारभूत आँकड़ों के संग्रह, एज़्सपोज़र विज़िट, विजुअल मैनेजमेंट पद्धतियों, रेड टैग प्रणाली, मानकीकृत लेआउट, सफाई अनुसूचियों, नियमित ऑडिट तथा काइज़न पहलों का समर्थन प्राप्त हुआ। इन प्रयासों से कार्यस्थल पर मापनीय और टिकाऊ सुधार सुनिश्चित हुए। इस पहल के परिणामस्वरूप सामग्री की खोज एवं प्राप्ति का औसत समय पाँच मिनट से घटकर मात्र 0.5 मिनट रह गया। प्रभावी स्थान अनुकूलन से कुल 1,080 वर्ग मीटर क्षेत्र की शुद्ध बचत हुई। 18 चिन्हित असुरक्षित स्थितियों के उन्मूलन से सुरक्षा प्रदर्शन में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ, जिससे संभावित जोखिम कम हुए और समग्र कार्यस्थल सुरक्षा में वृद्धि हुई। बेहतर संगठन एवं स्वच्छता से मशीनों की विश्वसनीयता तथा निवारक अनुरक्षण में भी सुधार हुआ।

अप्रचलित एवं अनावश्यक सामग्रियों के व्यवस्थित निपटान से उल्लेखनीय विज़ीय लाभ प्राप्त हुआ। 5एस एवं काइज़न पहलों के माध्यम से रोल शॉप-ढ्ढङ्क ने मात्र 31,200 रुपये की न्यूनतम कार्यान्वयन लागत के मुकाबले कुल 18,99,425 रुपये की लागत बचत हासिल की, जो उत्कृष्ट लागत-लाभ अनुपात को दर्शाता है।आरएसपी में 5एस विस्तार कार्यक्रम भी व्यापक रूप से चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत रोल शॉप-ढ्ढङ्क की टीम नए प्लेट मिल के मोटर हाउस, हॉट स्ट्रिप मिल-2 के मोटर हाउस तथा रोल शॉप-ङ्क सहित तीन अन्य विभागों को 5एस प्रथाओं के प्रभावी अंगीकरण एवं दीर्घकालिक स्थायित्व के लिए मार्गदर्शन एवं मेंटरिंग प्रदान कर रही है।क्वालिटी सर्कल टीम में श्री अंशुमन मिश्रा एवं श्री सैहून भेंगरा, दोनों कनिष्ठ अभियंता सहयोगी शामिल थे। टीम के फेसीलिटेटर, उप प्रबंधक, श्री एम के राजगुरु थे। इस परियोजना का कार्यान्वयन महाप्रबंधक प्रभारी (रोल शॉप), श्री समीर रंजन महापात्र तथा महाप्रबंधक (रोल शॉप), श्री मिहिर कुमार मुदलि के सतत पर्यवेक्षण एवं सक्रिय मार्गदर्शन में किया गया।टीम ने हाल ही में ग्रेटर नोएडा में आयोजित एनसीज़्यूसी में इस परियोजना की प्रस्तुति दी और प्रतिष्ठित 'पार-एज़्सीलेंस अवार्ड' प्राप्त किया।